HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 16-31 अगस्त, 2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 2/ अंक 27/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

यदि बूंद-2 से घड़ा भर जाता है तो छोटे-छोटे प्रयास मिल कर सफलता को सुनिश्चित करते है : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

मिशन रीव सेवा क्षेत्र में दुनिया का अनूठा प्रयास

रीव टाइम्स सबसे कम समय में बना पाठकों की पसंद

राउंड टेबल कंसल्टेशन में देश भर के विद्वानों ने दिए सुझाव

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

द रीव टाइम्स समाचार प्रकाशन के एक वर्ष पूरा करने पर तथा मिशन रीव के विगत एक वर्ष के आकलन पर राउंड टेबल कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईआईआरडी द्वारा शनान में मुख्य कार्यालय सभागार में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में अनिल कुमार सिन्हा, आई ए एस (सेवानिवृत) द्वारा बतौर मुख्यातिथि शिरकत की गई। सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार, मेंटोर व कंसल्टेंट, हज़ार्ड रिस्क मैनेजमेंट, क्लाईमेट चेंज अडेपटेशन एवं सस्टेनेबल डेवेलपमेंट है। सिन्हा बिहार आपदा प्रबन्धन के प्रमुख भी रहे हैं तथा वर्तमान में आपदा प्रबंधन पर ही सेवाऐं दे रहे हैं। उनके साथ हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार एवं आईएएस (सेवानिवृत) श्रीनिवास जोशी भी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वर्ल्ड बैंक ग्रुप से विनीता हरिहरण ने शिरकत की। युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से नेहरु युवा केन्द्र के संयुक्त निदेशक प्रभात कुमार ने भी भाग लिया। इसके अलावा शैल सूत्र की प्रधान संपादक एवं लेखिका आशा शैली भी इस कार्यक्रम में देहरादून से विशेष तौर पर शामिल हुईं। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से डॉ॰ सी बी तिवारी ने भी शिरकत की। यह कार्यक्रम दो भागों में विभाजित था जिसमें प्रथम सत्र में **मिशन रीव : आकलन एवं भविष्य की चुनौतियों पर मंथन एवं चर्चा** रखी गई थी। सर्वप्रथम आईआईआरडी के चेयरमैन प्रो॰ आर के गुप्ता ने समस्त विद्वत्जनों का स्वागत किया। उन्होंने मिशन रीव को अनूठा प्रयास बताते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर दस्तक देने के बाद अब समय आ गया है कि मिशन रीव को गांव-गांव में बेहतरीन सेवाओं के साथ हम लोगों तक ले जाने के लिए कामयाब हो।

मुख्यातिथि आई ए एस (सेवानिवृत) अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि मिशन रीव का प्रारुप भिन्न तो हैं किंतु आवश्यकता है कि इसको सरकार द्वारा संचालित लोकमित्र केन्द्रों एवं सामुदायिक केन्द्रों से भिन्न आम लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने की। उन्होंने कहा कि सेवा के क्षेत्र में मिशन रीव हिमाचल प्रदेश में मिसाल बन सकता है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर भी ऐसे प्रयास कर रही है लेकिन वो पर्याप्त और धरातल पर नहीं है। मिशन रीव का ख़ाका आम आदमी तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है, साथ ही मिशन रीव गांव-गांव में आदमी तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। साथ ही मिशन रीव ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन आदि पर भी सेवाऐं दे और लोगों को इसकी जागरुकता के लिए सेवाऐं दें।

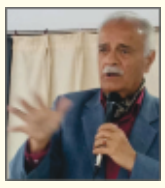

वरिष्ठ साहित्यकार श्रीनिवास जोशी ने कहा कि रुरेलाईजिंग शब्द पर उन्हें आपत्ति है। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी रुरेलाईजिंग क्यों ? साथ ही उन्होंने पूछा कि मेरी पंचायतों में मिशन रीव द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का विवरण क्या है ? उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना भी की और इसके संचालन के लिए सुझाव भी दिए।

भारत सरकार के एनवाईके से संयुक्त निदेशक प्रभात कुमार ने भी चर्चा में भाग लिया। उन्होंने मिशन रीव को युवाओं के लिए रोजगार आधारित कैसे बनाया जा सकता है, इस विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में युवा मंडल है और ये युवा मंडल नेहरु युवा केन्द्र से संबद्ध है जिससे मिशन रीव को अपने उद्देश्य में सफल होने में सरलता होगी। युवा मंडल के चयनित युवाओं को मिशन रीव का ब्रांड ऐंबेसडर बनाया जाना चाहिए तथा इसके लिए इस पूरी प्रक्रिया को रोज़गार से जोड़ना भी अति आवश्यक है

डॉ॰ एल सी शर्मा, प्रबंध निदेशक, आईआईआरडी ने मिशन रीव की पूरी यात्रा को आईटी आधारित सबसे बड़े प्रयास के रुप में सामने रखा जो अभी सरकारी महक़मों में संभव नहीं बन पाया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सदस्यता लेने के पश्चात् आवश्यकता आकलन होता है जो कि पूर्णतः आईटी आधारित है। उनके द्वारा चर्चा में लाये गए मुद्दों पर आमंत्रित अतिथियों द्वारा अनेक प्रश्न व जिज्ञासाऐं सामने रखी गई। इसमें मिशन रीव की एक वर्ष की उपलब्धियों और वांछित सफलता को प्राप्त न होने के कारणों पर भी प्रश्न पूछे गए।

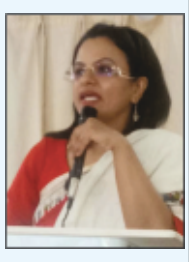

विश्व बैंक की अधिकारी विनीता हरिहरण ने मिशन रीव को विश्वस्तरीय अनूठी पहल बताते हुए कहा कि तकीनिक रुप से यह मिशन बहुत पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच में है। सेवा क्षेत्र में हालांकि अभी बहुत कुछ करना शेष है फिर भी इसका प्रारुप सर्वथा भिन्न है उन्होंने कहा कि उनका हरसंभव सहयोग इस मिशन के लिए मिलता रहेगा।

द रीव टाइम्स को बनना है जन-आवाज़, एक वर्ष रहा सराहनीय

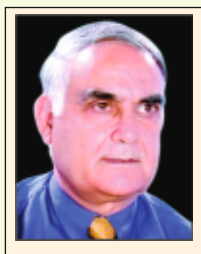

आईआईआरडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिगेडियर बीके खन्ना ऑस्ट्रेलिया से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने मिशन रीव के एक साल के सफर की सफलता पर आईआईआरडी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आईआईआरडी ने मिशन रीव के माध्यम से गांवों के विकास की एक अनूठी पहल की है जिसके लिए आईआईआरडी बधाई की पात्र है। ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा कि जिस तरह से मिशन रीव हिमाचल में गांवों की तस्वीर बदलने का प्रयास कर रहा है वह काबिले-तारीफ है। उन्होंने कहा कि मिशन रीव को वह वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। मिशन रीव के साथ -साथ उन्होंने 'द रीव टाइम्स' पाक्षिक समाचार पत्र का एक साल पूरा होने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार इस समाचार पत्र को पढ़ने का मौका मिला और यह समाचार पत्र बेहद आकर्षक और ज्ञानवर्धक है।

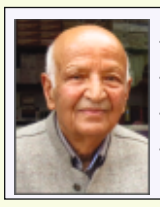

चेयरमैन आईआईआरडी प्रो॰ आर के गुप्ता ने द रीव टाइम्स ब्यूरो को बधाई दी और कहा कि ये प्रयास निरंतर जारी रहेंगे तथा समाचार पत्र जन आवाज़ बनकर पाठकों के लिए सेवाऐं देता रहेगा।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में **द रीव टाइम्स** के एक वर्ष पूरा होने पर **समीक्षा एवं प्रभावों पर मंथन** किया गया। प्रधान संपादक डॉ. एल सी शर्मा ने एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर पाठकों एवं समीक्षकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में द रीव टाइम्स इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी प्रदेश करने की योजना पर कार्य कर रहा है। परिचय सत्र में पूर्व प्रबंध संपादक आन्नद नायर ने कहा कि द रीव टाइम्स के आरम्भ करने के बाद एक वर्ष में आज पाक्षिक समाचार पत्र को पूरे देश में पाठकों को अपार स्नेह प्राप्त हो रहा है। संस्था 21 राज्यों में सेवाऐं दे रही है जिसमें द रीव टाइम्स भी वहां पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रयागराज से आए लेखक डॉ॰ सी बी तिवारी ने कहा कि द रीव टाइम्स ने पाक्षिक समाचार पत्र होने के बाद भी दैनिक समाचार पत्र की तरह पाठकों के दिल में स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसकी प्रतियों की संख्या में इज़ाफा करके इसे हर ज़िले में पहुंचाने की सुनिश्चितता बनाई जाए।

वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रख्यात लेखक श्रीनिवास जोशी ने आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए समाचार पत्र की ख़ामियों को भी उजागर किया और ये भी कहा कि इसमें सारगर्भित जानकारी पाठकों तक पहुंच रही है। उन्होंने विशेष रुप से पृष्ठ 13 पर सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए द रीव टाइम्स की सराहना की और कहा कि इससे न केवल ज्ञानवर्धन होता है बल्कि विद्यार्थियों और परीक्षा प्रतियोगिताओं में भी इस प्रकार की जानकारी से सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि यह समाचार पत्र सबसे उत्कृष्ट पन्नों और रंगीन प्रारुप के साथ प्रकाशित किया जा रहा है लेकिन पत्र-पत्रिकाऐं आकर कब विलुप्त हो जाती है, इसका भी एक इतिहास रहा है। इसलिए इस समाचार पत्र को भी दीर्घलालीन सेवाओं में रखने के लिए इसकी विषयवस्तु और प्रकाशन की अन्य आवश्यक बातों का ध्यान रखना होगा।

शैल सूत्र की प्रधान संपादक एवं वरिष्ठ साहित्यकार आशा शैली जो कि विशेष रुप से उत्तराखंड से कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आई थी, ने द रीव टाइम्स को एक वर्ष पूरा करने पर बधाई दी और प्रधान संपादक को जन भावनाओं एवं उनकी आवाज़ बनने के लिए शुभकामनाऐं दी। उन्होंने कहा कि पाक्षिक समाचार पत्र ने 16 पृष्ठों में लगभग प्रत्येक क्षेत्र को समाहित करने का सराहनीय प्रयास किया है।

जीवन के हर पहलु का आयना है 'मुझे बंद आंखों से देखो'

संपादक के पहले काव्य संग्रह का विमोचन

देश उबल रहा है..खून खौल रहा है...
और इसी तरह के क्रांतिकारी... *शेष पेज 3 पर*

Round Table Consultation on Analysing Mission RIEV & The RIEV Times

कार्यक्रम की झलकियां कैमरे की नज़र से

पेज 1 का शेष

जीवन के हर पहलु का आयना है 'मुझे बंद आंखों से देखो'

संपादक हेमराज चौहान के पहले काव्य संग्रह का विमोचन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

देश उबल रहा है..खून खौल रहा है...और इसी तरह के क्रांतिकारी शब्दों को समेटे 'शीष कटाना मोल रहा है' शीर्षक से छपी पहली ही कविता कवि के शेष काव्य संग्रह के विषय गंभीरता को स्पष्ट करने के लिए काफी है। यूं तो 'मुझे बंद आंखों से देखो' 61 कविताओं का संग्रह है लेकिन हर कविता में युवा कवि हेमराज चौहान ने मानव जीवन के उन पहलुओं को कविताओं में संजोया है जो किसी न किसी रूप में हर आदमी के जीवन से जुड़े हैं।

पेशे से पत्रकार, लेखक, समाजसेवक और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार समेत कई राज्य पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हेमराज चौहान के पहले काव्य संग्रह 'मुझे बंद आंखों

से देखो' का हाल ही में विमोचन किया गया। पहली कविता में कवि जहां अपनी क्रांतिकारी सोच से आम आदमी में देभभक्ति की भावना भरते हैं तो वहीं अगली कविता में हमारे समाज में कुंठित वर्ग पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूकते। पाखंड शीर्षक अपने आप में समाज के उस वर्ग पर कुठाराघात करने के लिए काफी है जो खुद को धर्म का ठेकेदार तो बताता है लेकिन धर्म की आड़ में बड़े अपराधों को अंजाम देने में व्यस्त है। 'नदी का पुल' उस भ्रष्टाचार को उजागर करता है जो आज हर जगह फलफूल रहा है। यह उन चंद शुरूआती कविताओं के शीर्षक है जो आंखे बंद होने पर भी हमारे सामने हमारे समाज की तस्वीर हमें आसानी से दिखाते हैं। इन शीर्षकों के अतिरिक्त भी 'मुझे बंद आंखों से देखो' काव्य संग्रह में इसी तरह की कुल 61 कविताएं हैं जिसमें अलग-अलग शीर्षक से मानव जीवन की कहानी कहने का सफल प्रयास कवि ने किया है।

आरटीओ कार्यालय के समीप भूस्खलन के बाद तीन की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शहर में भारी बारिश के बीच सुबह करीब साढ़े छह बजे आरटीओ कार्यालय के पास मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया । हादसे में मां और दो बेटियों की मलबे में दबने से मौत हो गई । इनकी पहचान कृष्णा (42), विशाखा (15) और दिव्या (18) के रुप में की गई है । पिता हरिदास (48) गंभीर रुप से घायल हो गए हैं । आरटीओ कार्यालय के समीप हादसा सुबह साढ़े छह बजे के करीब हुआ । कोटला धुन्धन अर्की के रहने वाला हरि दास अपने दो भाइयों के परिवार के साथ कच्चे मकान में रहता था । लेकिन सुबह अचानक भूस्खलन होने के बाद पत्नी व दो बेटियों के साथ मलबे में दब गए । वहीं इसी बीच भाई सुरेंद्र और बेटी चंचल बाहर निकल गए थे। लेकिन इस घटना में हरि दास की पत्नी और दो बेटियों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस व प्रशासन सुबह साढ़े 7 बजे मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान दो बच्चियों और पति को मलबे से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। जहां पर डॉक्टरों दोनों बेटियों को मृत घोषित किया वहीं पिता को उपचार दिया।

हालांकि दूसरी ओर हरि दास की पत्नी मलबे में दबी थी। जिन्हें कि कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला गया। जिसके बाद महिला की प्राथमिक जांच के बाद मृत घोषित किया गया।

किन्नौर में बारिश से करोड़ों का नुकसान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

किन्नौर जिला में बारिश से करीब 2,12.70 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार विभिन विभागों से मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर क्षेत्रों जिनमें रुंनग, चगांव, जानी उरणी, पानवी, सांगला पीओ शहर, तेलंगी के गांवों शामिल हैं में पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। इसके साथ ही शोंगथोंग से पुरबनी रोड, शोन्थोंग से बारंग रोड, टापरी, चगांव लिक रोड और उरनी रोड, टापरी चोलतु जानी, उरनी मीरू रंगले रोड, करछम सापनी रोड, रुतरंग ब्रिज से बोनिगसेयरिग रोड, करछम सांगला छितकुल रोड, चोरा रूपी से छोटा कम्बा रोड, निगुलसारी तरांडा रोड, वांगतू पनवी के लिक रोड गांवों की सड़कों को नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्पिलो, रिब्बा नाला, शिअशो ब्रिज, रुंनग नाला सड़कें बंद पड़ी हैं। किन्नौर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 1077 व दूसरा 0177 8622315 से लेकर 8622355 तक को 24 घंटे सूचना दी जा सकती है।

मीरू पंचायत प्रधान गीता ज्ञानी ने कहा कि मुकेश कुमार नेगी पुत्र काला सरन के मकान को भी नुकसान पहुंचा है। उरनी कंडे में 2000 से 2500 भेड़ बकरियों का कोई पता नहीं है। वहीं चगांव के पटवारी रविंद्र सिंह ने बताया कि टापरी में स्व. चेत राम पुत्र शरद नेगी, स्व. राजमन पुत्र कमान सिंह व सुखराम के मकान को मिलाकर कुल 12 लाख का नुकसान हुआ है।

सतलुज में सिल्ट बढ़ने से नाथफा झाखड़ी में बिजली का उत्पादन रुका, कहीं अंधेरा न हो जाए

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते ब्यास, सतलुज, सरसा समेत सभी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है । इन नदियों में गाद का स्तर काफी बढ़ गया है। इसके चलते देश के सबसे बड़े भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथफा झाखड़ी में बिजली का उत्पादन स्थगित कर दिया गया है। ऐसा सतलुज नदी की सहायक नदी भाबा खड्ड नदी में गाद की मात्रा बढ़ जाने के चलते किया गया है। किन्नौर जिला स्थित नाथफा झाखड़ी विद्युत परियोजना से 1500 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होता है। यहां बिजली का उत्पादन स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा शिमला जिले के रामपुर में विद्युत परियोजना के तहत 412 मेगावॉट का उत्पादन होता है, को भी फिलहाल स्थगित करना पड़ा है । विद्युत परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि किन्नौर जिले स्थित नाथफा झाखड़ी डैम के आसपास सतलुज में सिल्ट की मात्रा बढ़कर 8000 पीपीएम हो गई है । राज्य में बहने वाली नदियां खतरे के निशान से उपर बह रही हैं। गौरतलब है कि कांगड़ा जिले में इस साल 118 और धर्मशाला में 115 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है ।

मूसलाधार बारिश ने हिमाचल में मचाई तबाही, 490 करोड़ का नुकसान, अब तक 24 लोगों की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रदेश भर में भारी तबाही मचाई है। बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। खराब मौसम के चलते प्रदेश में सामान्य जन जीवन ठप होकर रह गया है। नदी नाले उफान पर हैं, नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। अब तक हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कई सड़कें बंद हैं। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। प्रदेश के छह जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश प्रशासन को करने पड़े हैं ।

70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा इस बार बारिश ने

प्रदेश में बारिश ने पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। जानकारों का मानना है कि इतनी बारिश उन्होंने कई साल पहले देखी है। प्रदेश में जानलेवा बरसात के कहर से अब तक कई जानें चली गई हैं। अनेक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश के नौ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 877 सड़कों पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। कालका-शिमला और पठानकोट -जोगिंद्रनगर रेल ट्रैक मलबा और पेड़ गिरने से ठप रहे। प्रदेश के तीनों एयरपोर्ट गगल, भुंतर और शिमला में हवाई उड़ानें प्रभावित रहीं। अगस्त माह में लहौल घाटी में हो रही बर्फबारी की वजह से करीब पर्यटक भी फंस गए ।

कोमली बैंक में बारिश से धंसी सड़क

ख़तरनाक पेड़ भी हो सकते है जानलेवा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कहर बरसाती बारिश ने सरकार और प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। महापौर व पार्षद कुसुम सदरेट के वार्ड के अंतर्गत कोमली बैंक में बारिश से जहां सड़क धंस गई है और उस पर अभी भी रिस्क पर वाहन चलाऐ जा रहे हैं जिससे कोई भी अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। साथ ही कोमली बैंक में ख़तरनाक पेड़ों से जान-माल का नुकसान होने का ख़तरा पैदा हो गया है । इन ख़तरनाक पेड़ों के गिरने का ख़ौफ क्षेत्रवासियों में बना हुआ है । इन पेड़ों को काटने अथवा उनकी छंटाई करने की गुहार अनेकों बार लिखित एवं मौखिक रुप से उद्घोष संस्था ने महापौर एवं प्रशासन को दी है। इसके बावजूद वन विभाग अथवा प्रशासन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। एक सूखा पेड़ तो किसी भी समय गिरने की के कगार पर हैं जो कि वहां स्थित मकानों पर गिरता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है । शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । यहां सड़क के साथ 5 से 10 पेड़ ऐसे हैं कि लगातार हो रही बारिश में कभी भी गिर सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है । सामाजिक संस्था उद्घोष इस बाबत महापौर से मिला था और लोगों ने मौका पर भी इस समस्या को बताया था । प्रशासन इस प्रतीक्षा में हैं कि जब कोई बड़ा हादसा होगा तभी उसकी नींद जागेगी ।

सामाजिक संस्था उद्घोष एवं समस्त क्षेत्रवासी निवेदन करते है कि इन ख़तरनाक पेड़ों को तुरंत काटा जाए और छंटाई की जाए ताकि जानमाल के नुकसान को रोका जा सके । लोगों में ख़ौफ है जिससे प्रशासन आंखे मूंद कर बैठा है । महापौर और जिलाधीश से निवेदन किया है इस समस्या पर शीघ्र ही नींद से जागे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करें ।

कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाया बड़ा क़दम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग आत्मा योजना के तहत पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहा है। कृषि विभाग किसानों को जो निशुल्क पौधे बांटता था, अब पौधे उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जिनके घर में गाय होगी। विभाग की मानें तो गांवों में भी अब कम लोग पशुपालन करते हैं। इस कारण भी प्राकृतिक खेती में कमी आई है। ऐसे में धीरे-धीरे विभाग बीज भी उन्हीं किसानों को देगा, जिनके घर में गाय होगी। शिमला के 11 ब्लॉकों में पौध वितरण शिविर जल्द लगाया जाएगा। कृषि विभाग उद्यान विभाग से पौधे लेकर किसानों को बांटेगा।

कृषि विभाग की मानें तो देसी गाय का गोबर और गोमुत्र हर प्रकार की खेती के लिए फायदेमंद होता है। गाय का गोमुत्र मनुष्य के शरीर की सारी बीमारियों के लिए भी कारगर है। पशुपालन और आवारा पशुओं की समस्या से निपटने को भी विभाग यह कदम उठा रहा है।

मशोबरा से शुरु की जाएगी योजना

मशोबरा में कृषि विभाग पहला शिविर लगाएगा । मशोबरा ब्लॉक में जिन लोगों के घर में गाय होगी, उनकी जानकारी लेकर विभाग पौधे बांटने का कार्य शुरू करेगा । इसके अलावा विभाग उन्हें प्राकृतिक खेती के तरीके भी बताएगा ।

मणिमहेश यात्रा पर रोक, लाहौल-स्पीति में बर्फबारी, हजारों मवेशी फंसे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारी बारिश के बाद जगह-जगह भूस्खलन के चलते प्रशासन ने पवित्र मणिमहेश यात्रा पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। भरमौर से सैकड़ों श्रद्धालुओं को वापस भेजा गया।

एसडीएम भरमौर पीपी सिंह ने कहा कि खराब मौसम और मार्ग बंद होने के कारण मणिमहेश यात्रा पर रोक लगाई गई है। मौसम अनुकूल होने पर ही यात्रा फिर शुरू होगी। हालांकि, आधिकारिक तौर पर मणिमहेश यात्रा 24 अगस्त से शुरू होनी है।

बीते दिन भी मणिमहेश यात्रा पर निकले 400 श्रद्धालु फंस गए थे। राठघार, बग्गा, जांधी, दिनकाधार, लाहल और दुर्गेठी के पास भूस्खलन होने से फंसे इन श्रद्धालुओं को घंटों मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया।

बारिश के बाद रिज पर मंडराया संकट, और लंबी हो गई दरारें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मूसलाधार बारिश के बाद ऐतिहासिक रिज मैदान पर दरकने का खतरा मंडरा गया है। गेयटी थिएटर के सामने करीब 15 मीटर लंबे रिज के हिस्से में पड़ी दरारें और ज्यादा बढ़ गई हैं। खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे के भीतर ही ये दरारें न सिर्फ चौड़ी हो गई हैं बल्कि 15 मीटर तक के हिस्से में पहुंच गई हैं। रिज के किनारे पर लगी रेलिंग टूटने लगी है। नगर निगम ने शनिवार को ही इन दरारों को सीमेंट लगाकर भर दिया था। लेकिन 24 घंटे के बाद ये दरारें और बढ़ गई हैं। निगम प्रशासन दावा कर रहा है कि रिज के धंसने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन भारी बारिश के बाद दरारें देखी गई हैं, उससे रिज पर संकट पैदा हो गया है। आने वाले दिनों में रिज पर पड़ी दरारों में पानी रिसने से इसके धंसने का खतरा और बढ़ सकता है। उधर, चौड़ा मैदान से एडवांस्ड स्टडी सड़क पर भी कई जगह दरारें पड़ गई हैं। इसे वन-वे कर दिया गया है। न्यू शिमला में भी सेक्टर चार के समीप सड़क पर लंबी दरार पड़ गई है। इसके कारण सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।

शहर में दर्जनों एंबुलेंस रोड बंद

शहर में भारी बारिश के बाद दर्जनों एंबुलेंस रोड बंद हो गए हैं। न्यू शिमला, भट्ठाकुफर, समरहिल, फागली, खलीनी, विकासनगर एरिया में कई सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। नगर निगम ने देर शाम तक राहतकार्य जारी रखे और ज्यादातर सड़कें बहाल कर दीं। आयुक्त पंकज राय की अगुवाई में अधिशासी अभियंता सुधीर गुप्ता, एसडीओ राजेश ठाकुर की टीमें अलग अलग इलाकों में डटी रहीं। निगम ने दो जेसीबी, दो रोबोट और 150 से ज्यादा कर्मचारी बचाव कार्य में लगा रखे हैं।

आईआईआरडी में दिया प्रशिक्षण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

युवा नेतृत्व और सकारात्मक सोच से कैस हम अपना जीवन बदल सकते हैं, इस पर एक दिवसीय कार्यशाला का अयोजन आईआईआरडी सभागार में आयोजित किया गया जिसमें प्रशिक्षक मनोज शर्मा मुख्य वक्ता शामिल हुए ।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

20 स्कीमें 15 पंचायतों की प्यास बुझाने में फेल

द रीव टाइम्स, ऊना

आईपीएच विभाग मंडल बंगाणा के तहत लोगों को पेयजल आपूर्ति घर-घर तक उपलब्ध कराने के लिए 20 पेयजल योजनाएं भी नाकाम सिद्ध हो रही हैं। साल के बारह महीनों में उपभोक्ताओं को महज दो माह ही पर्याप्त पानी उपलब्ध हो पाता है। बीते विस चुनावों में पेयजल एक ज्वलंत मुद्दा रहा। इसके बलबूते पर कुटलैहड़ की जनता को गुमराह किया गया लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद इस समस्या से निजात दिलाने को कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। हैरानी की बात है कि धुंदला जिला परिषद वार्ड के तहत 16 पंचायतें आती हैं। इनमें करीब 25 हजार की जनसंख्या है। 20 पानी की स्कीमों के जरिये धुंदला जिला परिषद बार्ड की प्यास बुझाने का प्रावधान है लेकिन लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध न होने के कारण प्यासा ही रहना पड़ता है। जब कभी भी कुटलैहड़ के किसी बाशिंदे से समस्या के बारे में पूछा जाता है तो सर्वप्रथम पेयजल संकट ही सबसे उपर होता है। लोगों का कहना है कि जब विभाग के बड़े अधिकारियों से इस बारे में बात की जाती है तो अक्सर स्टाफ की कमी का हवाला दिया जाता है या बिजली कट को कारण बताया जाता है। लोगों का आरोप है कि जिला के कई हलकों में एक दिन में दो बार पानी की आपूर्ति का प्रावधान है लेकिन कुटलैहड़ क्षेत्र के कई गांवों में सप्ताह भर भी पानी नहीं मिल पाता है। प्रशासन का तर्क है कि धुंदला जिला परिषद वार्ड के तहत 20 पेयजल स्कीमों से लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। जब कभी भी पानी की समस्या होती है तो इसके पीछे पाइप का क्षतिग्रस्त होना और बिजली के कटों का लगना कारण रहता है। इस बरसात के कारण विभाग को अब तक 80 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। जगह-जगह से सप्लाई पाइप क्षतिग्रस्त हैं। मरम्मत जारी है। जल्द ही पानी की समस्या से कुटलैहड़ की जनता को निजात दिला दी जाएगी।

जर्जर इमारत बन सकती है दुर्घटना का कारण

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

दौलतपुर चौक-ऊना मुख्य सड़क पर चलेट में जर्जर हवेलीनुमा पुरानी इमारत कभी भी गिर सकती है। इसके बावजूद प्रशासन इससे बेखबर बना हुआ है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने बताया कि जर्जर इमारत पुरानी है। इमारत के मालिक भी अब आते जाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से इमारत में बनी दुकानों को दुकानदार भी छोड़ चुके हैं। इमारत की छत से स्लेट गिरते रहते हैं। इससे कभी भी राहगीर चपेट में आ सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि भवन को असुरक्षित घोषित करके शीघ्रातिशीघ्र गिराया जाए। ग्राम पंचायत उपप्रधान सचदेव सिंह ने बताया कि जर्जर इमारत का मामला उनके ध्यान में आया है। पंचायत इस इमारत के मालिकों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। लोनिवि अधिकारियों का कहना है कि इमारत निजी है। अगर पंचायत उन्हें लिखित में इसे हटाने के लिए एनओसी जारी करके आग्रह करती है तो विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।

गिरि नदी में खनन जारी, एसडीएम पांवटा की छापेमारी

द रीव टाइम्स, सिरमौर

प्रतिबंध के बावजूद गिरी नदी में अवैध खनन जारी है। बीते दिनों एसडीएम पांवटा एलआर वर्मा ने अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में छापे मारे। इस दौरान अवैध खनन करते तीन ट्रैक्टर पकड़े गए। इनके संचालकों को 38 हजार जुर्माना किया गया। अवैध खनन के लिए नदी की ओर जाने वाले संवेदनशील संपर्क मार्ग को जेसीबी से खुदवा कर बंद करवाया गया है। एसडीएम पांवटा की कार्रवाई से अवैध खननकारियों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम पांवटा एलआर वर्मा को पांवटा साहिब के कुछ क्षेत्रों में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी। एसडीएम ने वीरवार को स्वयं छापे मारे। इस दौरान मानपुर देवड़ा गिरि नदी क्षेत्रों में तीन ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। इनके पास खनन से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद तीन ट्रैक्टर संचालकों से 38 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूली गई। मौके पर जेसीबी मशीन मंगवा कर एसडीएम ने नदी को जोड़ने वाले चोर रास्ते को ही बंद करवा दिया है। गौरतलब है कि हिमाचल और उत्तराखंड प्रशासन बरसात के दिनों में नदी-नालों के आसपास उतरने से हादसों की आशंका के चलते पहले ही चेतावनी जारी कर देता है। बावजूद इसके पांवटा क्षेत्र में यमुना नदी के अलावा बाता मंडी और मानपुर देवड़ा में गिरि नदी में अवैध खननकारी जान की परवाह किए बिना खनन में जुटे रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार खनन और वन विभागीय टीमों की दबिश जारी रही। इस दौरान कई ट्रैक्टरों के चालान कर चोर रास्तों को बंद करवाया गया। अब, एसडीएम पांवटा को मानपुर देवड़ा क्षेत्रों में दिनदहाड़े अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी। एसडीएम एलआर वर्मा ने खनन विभाग के अधिकारी और सिंघपुरा पुलिस चौकी टीम को मौके पर बुलाया। जेसीबी मशीन को मंगवा कर चोर रास्तों को खोद कर बंद करवा दिया गया।

अब अंब में मिलेगी आरबीजी व अल्ट्रा साउंड की सुविधा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर ने हाल ही में सिविल अस्पताल अंब में अल्ट्रा साउंड मशीन और आरबीजी मशीन का लोकार्पण किया। माता चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के सौजन्य से अंब अस्पताल में पंद्रह लाख से अल्ट्रासाउंड मशीन और दांतों के उपचार के लिए ढाई लाख रुपये से स्थापित आरजीबी मशीन का लोकार्पण किया। विधायक ने कहा कि शिखर की ओर हिमाचल का नारा भाजपा सरकार का ध्येय है। इसके लिए पूरे प्रदेश में समाज के हर वर्ग का समान विकास और सुविधा ही हमारा लक्ष्य है। अंब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन और आरजीबी मशीन उपलब्ध होने से अब स्थानीय लोगों के इसके लिए होशियारपुर और नंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिससे लोगों के धन और समय दोनों की बचत होगी।

कमरऊ पंचायत के आधा दर्जन गांव बिजली कटों से परेशान

द रीव टाइम्स, सिरमौर

शिलाई क्षेत्र के तहत कमरऊ पंचायत में आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण तीन महीनों से पावर कट से परेशान हैं। रोजाना लग रहे बिजली कट से परेशान ग्रामीणों ने बीते दिनों उपमंडल कार्यालय सतौन में जाकर रोश प्रकट किया। कमरऊ पंचायत के देंवला, गुइला, टिंबी, खुइनल, चंबियार और चंजोत के करीब 50 परिवार विद्युत समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले तीन महीनों से रोजाना पावर कट लग रहे हैं। रात होते ही बत्ती गुल हो जाती है। ग्रामीण कुलदीप, कर्म सिंह, ज्ञान सिंह, सुंदर सिंह, कपिल, दीपचंद, शांतिराम, रामलाल और मोहन सिंह ने बताया कि अंधेरा होते ही पावर कट लग जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि फ्यूज सप्लाई का लोड सहन नहीं कर पा रहा है। अंधेरा होने पर जैसे ही बिजली ऑन होती है तो ट्रांसफार्मर से फ्यूज उड़ जाता है। इसे ग्रामीणों को ही लगाना पड़ता है। ऐसे में बरसात में करंट का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव को आने वाली लाइन भी बहुत पुरानी है। पोल भी खराब हो चुके हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर सतौन सब डिवीजन पहुंचे, जहां लिखित शिकायत वरिष्ठ कर्मचारी के माध्यम से सहायक अभियंता को दी गई। ग्रामीणों ने विभाग को लिखित चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो ग्रामीण सड़कों पर बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली के लिए उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार होगा। सहायक अभियंता ने बताया कि उन्हें शिकायत की जानकारी मिली है। कर्मचारी को मौके पर भेजकर पूरी जानकारी ली जा रही है। इस समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।

सोलन में संदिग्ध के घूमने से अभिभावक परेशान

द रीव टाइम्स, सोलन

सोलन में बीते कुछ दिनों से कई संदिग्ध देखे जा रहे हैं। ये संदिग्ध अक्सर बच्चों से बाते करते हुए देखें गए हैं। ऐसे में अभिभावक अपने नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतत है। कुछ दिन पूर्व ही बसाल और डांगरी पंचायत के गांवों में बीते दिनों दो संदिग्ध व्यक्ति दिखने के बाद क्षेत्र में अफरातफरी मंच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने मौके पर पहुंच कर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन देर रात तक लोगों के हाथ खाली रहे। जानकारी के अनुसार बसाल पंचायत के देवली की सैर गांव में देर रात करीब 09 बजे एक घर में कुछ संदिग्ध लोग आए, घर की एक महिला ने जब उन्हें देखा तो वह चिल्लाने लग गई। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पहुंच गए और इसकी सूचना गांव के अन्य लोगों को भी दी गई। इस पर गांव देवली की सैर, मोली, नालटू, भुलग, उपली पाट्टी, निचली पाट्टी, डांगरी के करीब 100 लोगों सहित पुलिस टीम साथ लगते क्षेत्र सहित जंगलों में इन संदिग्धों की तलाश में जुट गई, लेकिन देर रात करीब 12 बजे तक पूरे क्षेत्र सहित जंगल में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा। इसके बाद सभी लोग अपने-अपने घर वापस आ गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी और सनसनी का माहौल रहा।

लोग रात के समय अपने घर से बाहर जाने में डरने लगे हैं। उधर, एएसपी सोलन शिव कुमार ने बताया कि झूठी अफवाहों से बचने की अपील की है, उन्होंने बताया पुलिस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन लोग सोशल मीडिया की झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, तो इसकी सूचना पुलिस को दे और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े जाने पर उसके साथ मारपीट ने करें।

वाटर प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी, आरोपी फरार

द रीव टाइम्स, सोलन

पुलिस ने थाना अर्की के अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। कुनिहार के एक व्यक्ति ने उसके बेटे के साथ वाटर प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी की शिकायत पुलिस को दी है। शिकायत में चेतराम पुत्र बृजलाल निवासी हाटकोट बस स्टैंड कुनिहार ने कहा कि सचिन पुत्र विनोद कुमार निवासी 728 एलिमेंट्स मॉल डीसीएम अजमेर मार्ग जयपुर राजस्थान ने उसके लड़के को झांसे में लेकर लाखों रुपये की ठगी की है। पीड़ित के अनुसार सचिन ने उसके बेटे पंकज को बताया कि वह पान पराग कंपनी का अधिकृत डीलर है और हिमाचल में वह कंपनी की मदद से वाटर प्रोजेक्ट लगवा सकता है। इस प्रोजेक्ट के लालच में फंसकर पंकज ने बैंक से ऋण लेकर और खुद के पास जमा पैसे एकत्र कर करीब 15 लाख रुपये सचिन को दे दिए। इन पैसों को लेने के बाद सचिन लापता हो गया और अब वह उनका फोन भी नहीं उठा रहा है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी सचिन ने उनके बेटे से धोखाधड़ी करके पैसे हासिल किए हैं। उनका आरोप है कि पैसे लेते समय जो शर्तें रखी गई थीं, उन्हें भी पूरा नहीं किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अर्की थाना के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 406 व 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपी का पता लगाया जाएगा और उसे कानून के दायरे में लाकर पूछताछ की जाएगी। उधर, पीड़ित चेतराम ने बताया कि लाखें रुपये लुटने के बाद उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों संकट खड़े हो गए हैं। बेटे ने स्वरोजगार की चाहत में पैसे लगाए थे लेकिन उससे ठगी हुई है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

बीबीएन में नए मरीजों में मिले डेंगू के लक्षण

द रीव टाइम्स, सोलन

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में डेंगू अपने डंक से लोगों को बीमार कर रहा है और मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य खंड नालागढ़ के तहत बीबीएन में डेंगू के रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। इसमें दो नए मरीज डेंगू के लक्षण पाए हैं। नालागढ़ अस्पताल में एलीजा विधि से किए 22 परीक्षणों में से दो मरीज पॉजिटिव मिले हैं। ये दोनों मरीज बद्दी क्षेत्र से संबंधित बताए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में डेंगू के अब तक आठ मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। बीबीएन में कई मामले डेंगू के प्रकाश में आए थे और उससे पहले भी डेंगू ने बीबीएन में लोगों को अपना शिकार बनाया था। इसके लिए हेल्थ टीम ने बीबीएन का दौरा करके उपचार किया था। इस साल फिर डेंगू क्षेत्र के लोगों को डंक दे रहा है। नालागढ़ अस्पताल के एमडी मेडिसिन ने बताया कि डेंगू बीमारी अलग किस्म के मच्छरों के काटने से फैलती है और मच्छर खड़े साफ पानी में पनपते हैं। यह सुनहरे रंग का धारीधार मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू होता है। उधर, बीएमओ नालागढ़ ने कहा कि स्वास्थ्य खंड नालागढ़ के तहत दो नए मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। अब बीबीएन में डेंगू के आठ मरीज हो चुके है जिन्हें उपचार दे दिया गया है। इसकी रिपोर्ट बनाकर आला अधिकारियों को भेज दी गई है।

29 लाख के धोखाधड़ी मामले में मुख्य सरगना गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

कालाअंब पुलिस और साइबर शाखा की संयुक्त टीम ने 29 लाख रुपये के धोखाधड़ी मामले में बैटरी गिरोह गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। सिरमौर पुलिस ने शातिर अपराधी प्रशांत गुप्ता को कोलकाता से दबोचा। गैंग के तीन सदस्य सिरमौर पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस पिछले लंबे समय से मुख्य सरगना को दबोचने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार सिरमौर पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में बैटरी बनाने वाली एक कंपनी के मालिक को बैटरी गिरोह ने 29 लाख का चूना लगाकर ठगी का शिकार बनाया था। कालाअंब में स्थित बैटरी की फैक्टरी में पुरानी बैटरियों को खरीद कर उनमें लेड (सिक्के) को दोबारा प्रयोग करने लायक बनाया जाता है। कंपनी के मालिक को ठगों ने फोन कर पुरानी बैटरी 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने के बारे में बताया। कंपनी मालिक ने भी इस सौदे में दिलचस्पी दिखाई और बैटरियां खरीदने के लिए अपनी हामी भर दी। बैटरियों का कुल वजन 40 मीट्रिक टन के आसपास था। इनकी कीमत लाखों में थी। ठगों ने मालिक को विश्वास में लेने के लिए जीएसटी नंबर और कुछ अन्य कागजात भी भेजे। साथ ही ट्रक में लोड बैटरियों की फोटो भी मालिक को भेजी। इसके बाद ठगों ने राशि बैंक खाते में जमा करने के लिए कहा। कंपनी मालिक ने ठगों के कहने पर अलग-अलग किस्तों में कुल 29 लाख रुपये उनके खाते में डाल दिए। कई दिन बीत जाने के बाद भी बैटरियों की डिलीवरी नहीं मिली।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अब फिर हरियाणा से जुड़े लिखित परीक्षा में गड़बड़ी के तार

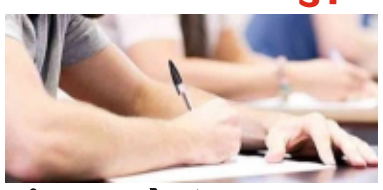

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

फरवरी महीने में पालमपुर में आयोजित सेना भर्ती सामान्य ड्यूटी की लिखित परीक्षा में गड़बड़ी होने के मामले के बाद एक बार फिर अब पुलिस भर्ती में हरियाणा के नाम सामने आया है। परौर में पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में दूसरे के स्थान पर पेपर देने आए युवाओं में अधिकतर हरियाणा के हैं, जबकि सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में भी हरियाणा के अंबाला का एक कोचिंग सेंटर चलाने वाला विजिलेंस टीम ने पकड़ा था। अब पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में भी हरियाणा के शूटर पकड़े हैं। ऐसे में कांगड़ा पुलिस अब हर दिशा में गंभीरता से जांच में जुट गई है। लिखित परीक्षा में कांगड़ा के युवाओं से संपर्क करने वालों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार हिमाचल के युवाओं से संपर्क कर आगे डील करने वाला स्थानीय निवासी हो सकता है। इसलिए पुलिस पकड़े गए युवाओं से इस मामले में गंभीरता के साथ पूछताछ करने में जुटी है। एसपी कांगड़ा ने कहा कि लिखित परीक्षा के दौरान पकड़े युवाओं से पुलिस सख्त पूछताछ कर रही है। जल्द मामले के मुख्य आरोपी को पकड़ा जाएगा।

बिलासपुर में स्क्रब टायफस ने जकड़े लोग, विभाग ने जारी किया अलर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर जिले को स्क्रब टायफस ने जकड़ लिया है। अभी तक जिला में करीब 100 मरीजों में स्क्रब टायफस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से कुछ मरीज जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं तो कुछ मरीज शिमला आईजीएमसी में उपचाराधीन हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर ने अभी तक 830 मरीजों का स्क्रब टेस्ट भी कर लिया है। इनमें से कुल 93 स्क्रब से पीड़ित हैं। इस तरह बिलासपुर जिले में तेजी से बढ़ता जा रहा स्क्रब टायफस आने वाले समय के लिए खतरनाक सिद्ध होता जा रहा है। वहीं, मामले की पुष्टि करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परविंद्र सिंह ने बताया कि विभाग ने जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग की टीमें जिलेभर में लोगों को जागरूक करने के लिए घरद्वार जा रही है। इसके चलते आए दिन जिला अस्पताल में स्क्रब से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्क्रब टायफस के लिए निरूशुल्क टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अगर किसी भी मरीज में स्क्रब टायफस के लक्षण पाए जा रहे हैं तो चिकित्सक उनके तुरंत स्क्रब टायफस के टेस्ट कर रहे हैं।

स्क्रब टायफस के लक्षण

तेज बुखार जो 104 से 105 डिग्री, सिर और जोड़ो में दर्द व कंपकंपी के साथ बुखार, शरीर में ऐंठन, अकड़न या शरीर टूटा हुआ लगना, अधिक संक्रमण में गर्दन, बाजूओं के नीचे, कूल्हों के ऊपर गिल्टियां होना इत्यादि स्क्रब टायफस के लक्षण हैं।

स्क्रब टायफस के लिए रोकथाम

खेतों, झाड़ियों एवं घास में काम करते समय पूरा शरीर ढककर, शरीर में सफाई का ध्यान रखना, घर तथा आसपास के वातावरण को साफ रखना, घर के चारों ओर घास, खरपतवार नहीं उगने दें, घर के अंदर और आसपास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें।

जनमंच में 55 शिकायतें, 50 का निपटारा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

उपमंडल फतेहपुर के राजा का तालाब में 16वें जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनमंच में विभिन्न विभागों की 55 शिकायतें आईं। इनमें से 50 का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि पांच शिकायतों को संबंधित विभागों को दस दिन के अंदर हल के निर्देश दिए। जनमंच में अधिकतर शिकायतें भूमि, पानी, बिजली, सड़क और पौंग बांध विस्थापितों से संबंधित रहीं। छत्र जोगियां गांव के कृष्ण सिंह पुत्र तीर्थ राम ने अपनी शिकायत में कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में उन्होंने संबंधित विभाग को 25 जुलाई 2018 को लिखित शिकायत दी थी, परंतु संबंधित क्षेत्र के कानूनगो ने टालमटोल की। उन्होंने कहा कि जब तक तहसील में बड़ा तहसीलदार नहीं आता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं, 92 साल के चुनी लाल निवासी ढ़सोली ने बताया कि 18 नंबवर 2013 को उन्होंने निशानदेही के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक विभाग इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं कर पाया है। सेवानिवृत्त सूबेदार जसवंत सिंह ने कहा कि उसने तीन साल से निशानदेही के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, आज तक कुछ नहीं हुआ है। सेवानिवृत्त कानूनगो हरी सिंह ने अपनी भूमि से संबंधित शिकायत पर कहा कि विभाग से बार-बार कहने पर भी उनकी शिकायत पर कोई प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई। इसके अलावा वचन सिंह, बिहारी लाल ने कहा कि उसके घर में पानी की समस्या है। तलाड़ा निवासी देश राज ने बताया कि उनके गांव के दस से ज्यादा घरों को भी पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नरेश गुलेरिया निवासी नेरना ने बताया कि उनके घरों को जाती विद्युत लाइन काफी लंबी है।

सीर खड्ड में पानी का स्तर बढ़ने से दस योजनाएं प्रभावित

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

घुमारवीं में सीर खड्ड में जल स्तर बढ़ जाने के कारण क्षेत्र की करीब एक दर्जन परियोजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। खड्ड में सिल्ट बढ़ जाने के कारण पानी नहीं उठ पा रहा है। इस कारण क्षेत्र में पानी के लिए भरी बरसात में भी हाहाकार मचा हुआ है। क्षेत्र के लिए रोज करीब आठ लाख लीटर पानी की जरूरत है लेकिन अभी कड़ी मशक्कत के बाद भी 2.32 लाख लीटर पानी ही फिल्टर हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है। इससे घुमारवीं उपमंडल के लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाली सीर खड्ड में पानी का स्तर बढ़ गया है। पानी अधिक मटमैला होने के कारण इसमें सिल्ट की अधिकता रही। इसके कारण खड्ड पर बनी उठाऊ पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं से पानी नहीं उठाया जा सका। सीर खड्ड में सिल्ट अधिक होने के कारण अन्य स्कीमों के साथ घुमारवीं शहर को पानी उपलब्ध करवाने वाली स्कीमें सेऊ, बद्धाघाट, नसवाल, पनोल, सोई सील बाड़ी, करंगोड़ा, हटवाड़, भराड़ी, लढयानी, पन्याला, औहर, लंझता व मझासू सहित अन्य उठाऊ पेयजल स्कीमें प्रभावित हुईं हैं। जबकि भदरोग व बड्ड सिंचाई योजनाएं भी खड्ड में आए मटमैले पानी के कारण प्रभावित रहीं। पानी की योजनाएं प्रभावित होने से उपमंडल के उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों को पेयजल के लिए हैंडपंपों व अन्य संसाधनों के सहारे रहना पड़ा। हालांकि शहरी क्षेत्रों में तो पेयजल आपूर्ति देने की व्यवस्था की जा रही है लेकिन नगर परिषद के साथ लगते कई ग्रामीण क्षेत्रों में पांच दिनों से पेयजल आपूर्ति पूर्णतया ठप है। इसके चलते इन क्षेत्र के लोगों को मजबूरन 500 रुपये प्रति टैंक के हिसाब से पानी खरीदना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीर खड्ड के पानी से सिल्ट निकालने के लिए एक करोड़ 80 लाख लागत से माइक्रो स्टीनर स्थापित किए हैं जो मटमैले पानी को फिल्टर करते हैं लेकिन बरसात के दिनों में सीर खड्ड में सिल्ट का स्तर 10000 पीपीएम तक पहुंच जाता है जिसके चलते पानी को लिफ्ट नहीं किया जा पाता।

नेरी गांव के दर्जनों परिवार आ सकते हैं बाढ़ की चपेट में

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

सीर खड्ड के तटीकरण में हो रही देरी के कारण नेरी गांव के दर्जनों परिवार बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। बरसात के मौसम में लोग डर के साये में रातें गुजारने को मजबूर हैं। प्रशासन ने अगर शीघ्र ही कोई उचित प्रबंध नहीं किया तो आने वाले दिनों में बाढ़ से कोई भी घटना घटित हो सकती है। स्थानीय लोग अभी तक 2007 में खड्ड में आई बाढ़ को नहीं भूले हैं। 2007 में नेरी गांव से होता हुआ बाढ़ का पानी साथ लगते चंदरूही कस्बे में फैल गया था। इससे दुकानदारों का लाखों का सामान खराब हो गया था। वहीं, पानी में पेट्रोल पंप की सुरक्षा दीवार बह गई थी। अब हालात फिर वैसे ही हैं। नेरी में खड्ड किनारे लगाई गई क्रेट वॉल धंस गई है। कभी भी खड्ड का पानी खेतों सहित गांव में घुस सकता है। लोगों में सीर खड्ड का तटीकरण किए जाने की योजना ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन कार्य सात साल बाद भी शुरू नहीं हो सका। इससे लोगों में रोष पनप रहा है। स्थानीय लोगों में रोशन लाल, विनोद कुमार, राकेश, दलीप सिंह, रजिंद्र कुमार और विजय आदि ने प्रदेश सरकार से जल्द खड्ड का तटीकरण करने की मांग उठाई है। उधर, ग्राम पंचायत ककड़ की प्रधान आशा देवी ने कहा कि लोगों को बाढ़ का भय सता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को समस्या से अवगत करवाया जाएगा।

आदर्श गांव दकड़ी को आज तक नहीं मिल पाई सड़क सुविधा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

शहर के साथ सटे स्वतंत्रता सेनानी के दकड़ी गांव को आजादी से 72 साल बाद भी सड़क सुविधा नहीं मिल पाई। कहने को तो आदर्श गांव है लेकिन गांव आज भी मूलभूत सुविधा को तरस रहा है। मजबूरी में स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को अपना पैसा खर्च कर अपने घर तक सड़क बनाने को मजूर होना पड़ा। स्वतंत्रता सेनानी का परिवार का घर घुमारवीं नगर परिषद के वार्ड नंबर सात दकड़ी में पड़ता है। स्व. स्वतंत्रता सेनानी परस राम गुप्ता दकड़ी गांव से संबंध रखते था तथा इस परिवार के लोगों ने इस सड़क के लिए कई बार स्थानीय व जिला प्रशासन के पास अपना दुखड़ा रोया पर प्रशासन का दिल न पसीजा और झूठे दिलासे देकर ही परिवार वालों को चलता किया गया। परिवार ने पहले स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर व पूर्व में विधायक रहे राजेश धर्माणी के पास भी सड़क सुविधा के लिए गुहार लगाई थी पर नतीजा आश्वासनों तक ही सीमित रहा है।

स्किन ओपीडी में ईलाज के लिए मरीजों को लगाने पड़ रहे चक्कर

द रीव टाम्इस ब्यूरो, हमीरपुर

डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर की त्वचा रोग ओपीडी में उपचार करवाने आने वाले मरीजों को पूरे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ समय पूर्व ही अस्पताल प्रबंधन ने त्वचा रोग की ओपीडी को नए (रेडियोलॉजी) भवन में शिफ्ट किया है। इस नए भवन में ओपीडी शिफ्ट तो हो गई, लेकिन ओपीडी में इलाज के लिए पर्चियां अभी भी पुराने भवन के प्रथम तल पर ही बनाई जाती हैं। इस कारण मरीज पहले पुराने भवन के प्रथम तल पर पर्ची बनवाता है। इसके बाद वह दोबारा अस्पताल के बाहर से करीब तीन सौ मीटर दूर स्किन ओपीडी में जाता है। ओपीडी में चिकित्सकों की ओर से उसे दवाई लिखे जाने के बाद वह फिर निःशुल्क दवाई काउंटर पर पुराने भवन के प्रथम तल पर आता है। इससे उसके तीन चक्कर स्किन ओपीडी में उपचार करवाने के लिए अस्पताल परिसर के ही लग जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को होती है। एक या डेढ़ घंटे की बजाय उपचार के लिए उन्हें चार से पांच घंटे अस्पताल में ही लग जाते हैं। ओपीडी के नए भवन में होने के कारण उन्हें इसका पता नहीं चल पाता है। इस कारण वह लोगों से पूछकर ओपीडी के लिए चक्कर काटते रहते हैं। इसके अलावा स्त्री रोग विभाग की ओपीडी भी प्रथम और द्वितीय तल के रास्ते के साथ होने के कारण यहां मरीजों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में लोगों को प्रथम तल से द्वितीय तल जाने में परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों में रमेश कुमार, विनोद कुमार, आशीष कुमार, अभिषेक, अखिल कुमार आदि ने आईजीएमसी की तरह स्किन ओपीडी के साथ ही एक पर्ची काउंटर बनाने की मांग की है ताकि दूर स्थित इस ओपीडी के साथ ही पर्ची बन सके और लोगों को लाभ मिल सके। एमएस डॉ. अनिल वर्मा का कहना है कि करीब तीन माह पूर्व ही ओपीडी को शिफ्ट किया गया है। लोगों को उचित सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर समस्या है तो इस बारे में प्रबंधन से चर्चा की जाएगी।

बाजार में रातोंरात शराब का ठेका खोलने पर भड़के लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

विकास खंड झंडूता की ग्राम पंचायत मलांगण के बाजार में रातों रात शराब का ठेका खोलने के कारण ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उक्त ठेका घरों के नजदीक खोल दिया गया है जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक से भी कर दी है। लोगों ने साफ कर दिया है कि ठेके को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गांव के नसीम मोहम्मद, नूरदीन, शबाना, सलमा, लियाकत अली, राजकुमारी, संतोष कुमारी, सुनीता देवी, रजनी देवी सहित अन्य ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक व एसडीएम झंडूता को एक पत्र के माध्यम से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनके घरों के पास शराब का ठेका खुलने से महिलाओं व बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही स्कूल, मुस्लिम बस्ती व मस्जिद भी हैं जहां पर ठेका खोलना अनुचित है। उन्होंने कहा कि ठेका खोलने से वहां का माहौल खराब होगा। शराबी ठेके पर से शराब लेकर वहीं पीना शुरू कर देते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उक्त ठेके को वहां से बंद करवाया जाए ताकि गांव का माहौल शांतिपूर्ण व स्वच्छ बना रहे। उधर सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ने बताया कि उन्हें इसकी शिकायत मिली थी। इस पर वह मौका पर गए और का निरीक्षण कर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के भीतर ग्रामीणों की सहमति से दूसरी जगह ठेके को स्थानांतरण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आबकारी नियम के तहत ठेके को वहां खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामीणों की दिक्कत को देखते हुए ठेके को वहां से दूसरी जगह रिहायशी बस्ती से दूर स्थानांतरण कर दिया जाएगा।

लोनिवि हमीरपुर के सर्कल के 11 टेंडर किए रद्द, अब दोबारा होंगे टेंडर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

लोक निर्माण विभाग हमीरपुर सर्कल के तहत सड़कों के 11 टेंडर रद्द हो गए हैं। स्वीकृत लागत से बहुत कम रेट भरने, तकनीकी शर्तों को पूरा न करने तथा कांट्रेक्ट की शर्तों को पूरा न करने पर लोनिवि ने यह कार्रवाई की है। अब यह सभी 11 टेंडर दोबारा नए सिरे से होंगे। हमीरपुर सर्कल में करीब एक दर्जन विभिन्न कार्यों के टेंडर रद्द होने से ठेकेदारों में हड़कंप है। वहीं, सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में लिए जा रहे लोनिवि के इन फैसलों की प्रशंसा हो रही है। लोनिवि ने निर्धारित विभागीय शर्तों को पूरा करने वाले 18 टेंडर सरकारी ठेकेदारों को आवंटित किए हैं। इसके साथ ही लोनिवि मुख्य अभियंता कार्यालय में सात अन्य टेंडरों की प्रक्रिया अभी चल रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के उन्नयन कार्यों के लिए केंद्र सरकार से 121 करोड़ रुपये की अभी हाल ही में स्वीकृति मिली है। बजट की स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने हमीरपुर सर्कल के तहत आने वाले सभी पांचों मंडलों धर्मपुर, हमीरपुर, भोरंज, टौणीदेवी और बड़सर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। जिसमें ब्लैक स्पॉट को खत्म करने, डंगे, पुलियों और सड़क को चौड़ा करने समेत 9 बड़े पुलों का निर्माण कार्य शामिल है। उधर, लोनिवि के अधीक्षण अभियंता ई. एनपीएस चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार से बजट की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया जारी है। निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने पर विभाग ने 11 टेंडर रद्द किए हैं। अब यह टेंडर दोबारा नए सिरे से होंगे। जबकि 18 टेंडर अवार्ड हो चुके हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मिशन रीव ने गांव के लोगों के साथ किया पौधारोपण

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

मिशन रीव की ओर से पंचायत के विकास में अहम योगदान दिया जा रहा है। पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों में सहयोग देने के साथ-साथ अब मिशन रीव पंचायतों को हरा-भरा बनाने में भी अपना योगदान दे रहा है। इसके लिए हाल ही में शिमला से पौधारोपण अभियान की शुरूआत की गई। इसके बाद प्रदेश के दूसरे जिलों की पंचायत में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला चंबा में भी पौधारोपण किया गया। इसमें महला ब्लॉक की विभिन्न पंचायत में सहायक ब्लॉक समन्वयक विनोद की अगुवाई में मिशन रीव की टीम ने पौधारोपण किया। मिशन रीव की इस पहल की पंचायत के लोगों की ओर से खूब प्रषंसा की जा रही है। एबीसी विनोद ने बताया कि मिशन रीव की ओर से मिशन रीव की ओर से चंबा में कई कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक लोगों को कई तरह की सेवाएं उनके घर-द्वार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने समेत अन्य कई तरह की सेवाएं गांव में लोगों को दी जा रही है। बरसात के मौसम में पंचायतों में लोगों को मिशन रीव के तहत पौधारोपण के लिए जागरूक किया जा रहा है और पौधारोपण भी किया जा रहा है।

कुल्लू में प्रतिबंध के बावजूद करवाई जा रही पैराग्लाइडिंग

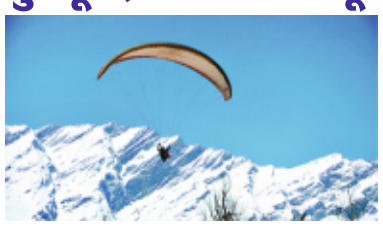

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

बरसात में हादसों के खतरों को देखते हुए प्रशासन व विभाग ने साहसिक गतिविधियों पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग आदि पर 15 सितंबर तक अधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन और विभाग की रोक के बावजूद कुल्लू जिले के मनाली में पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही जिससे हादसे पेश आ रहे हैं। प्रशासन के आदेशों की परवाह न कर पैराग्लाइडर करवाने वाली एजेंसियां पैसा कमाने में जुटी हैं। एजेंसियां चंद पैसों के लिए पर्यटकों की जान पर भारी पड़ रही है। ऊझी घाटी में बीते 10 अगस्त को पैराग्लाइडर क्रैश हो गया। पैराग्लाइडर क्रैश होने से इसमें एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि हादसे में पायलट की हालत गंभीर बनी हुई है। पैराग्लाइडर का यह हादसा पर्यटन नगरी मनाली के शनाग में हुआ। अब जब प्रशासन की ओर से पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पर पाबंदी लगाई गई है तो किसकी इजाजत से पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। यह विधानसभा क्षेत्र वन, परिवहन, युवा सेवाएं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का है। वन मंत्री के विस क्षेत्र में ही में पैराग्लाइडिंग करने वाले सरकार व प्रशासन के आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। बरसात के मौसम में ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है। इसमें रिवर राफ्टिंग व अन्य साहसिक गतिविधियां खतरे से खाली नहीं होती हैं। बरसात में कुल्लू घाटी में पैराग्लाइडिंग भी काफी खतरनाक है। ऐसे में हर वर्ष कुल्लू जिले में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक इन साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है। लेकिन इस रोक का असर कुल्लू जिले में नहीं हुआ है।

सुरक्षित नहीं देवी-देवताओं की करोड़ों की संपत्ति

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

देवभूमि कुल्लू के देवी और देवता करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। अधिकतर मंदिरों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। कई मंदिरों में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगे हैं। देवताओं के मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। इससे देव समाज चिंतित है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक कुल्लू के देवताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी कुल्लू में देवताओं के मंदिरों में चोरी हुई है। जिले के आराध्य देवता भगवान रघुनाथ, बिजली महादेव मंदिर से दानपात्र चोरी होने सहित अन्य मंदिरों में चोरी की वारदातें इससे पहले सामने आ चुकी हैं। देव समाज देवभूमि में बढ़ रही चोरी की वारदातों से सहमा हुआ है। दो दिन पूर्व खराहल के जुआणी महादेव मंदिर में हुई चोरी के आरोपी अभी पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाए हैं। जिला देवी-देवता कारदार संघ के महासचिव नारायण सिंह चौहान ने कहा कि मंदिरों में चोरी की वारदातें चिंता का विषय है। कारदार संघ ने सभी कारदारों को आग्रह कर रखा है कि मंदिर में सुरक्षा के लिहाज से गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरा लगाएं

कुल्लू में बादल फटने से तबाही

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कुल्लू में बादल फटने के बाद लोगों में दहषत का माहौल बना हुआ है। बीते 9 अगस्त को कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के कटागला गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई। उसके बाद भी लगातार बरसात का कहर जारी है। 9 अगस्त को सुबह करीब पांच बजे जैसे ही बादल फटने से नाले में बाढ़ आई तो लोगों में अफरातफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए साथ लगती पहाड़ी पर जा पहुंचे। छह घंटे बाद सुबह 11 बजे नाले का प्रवाह कम हुआ तो लोगों ने चैन की सांस ली। बादल फटने से दो पुल और सैकड़ों बीघा कृषि भूमि बह गई। घरों व सेब बगीचों में मलबा घुस गया है। पेयजल पाइप लाइन बहने से गांव में जलसंकट हो गया है। ता दें कि बीते साल 12 अगस्त को भी इसी गांव में बादल फटा था। बीते दिन किन्नौर के पूह खंड के कानम गांव में बादल फटने से बागवानों को करोड़ों नुकसान हुआ है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

आंगनबाड़ी केंद्रो में रोजगार का मौका, आवेदन आमंत्रित

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पदों पर आवेदन मांगे हैं। परियोजना अधिकारी सुंदरनगर (मंडी) कृष्ण पाल शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए पंचायत चुमुखा में केंद्र भंगलेहड़ा, जुगाहण, धन्यारा केंद्र, कलाहोड़ केंद्र में पद भरे जाएंगे।आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भनवाड़ के पटयोड़ा केंद्र, सलवाणा के गमोहू-1 केंद्र, रोहांडा के थाच केंद्र, अपर बैहली केंद्र, कपाही केंद्र, खिलड़ा के डडोली केंद्र, बलग के शलग केंद्र, महादेव के धनोटू केंद्र, जड़ोल के भवाणा केंद्र, चमुखा केंद्र, कांगू के सनोह केंद्र, सोझा के बतोल केंद्र, धन्यारा केंद्र सहित नगर परिषद के वार्ड नंबर भड़ोह के भड़ोह-1 केंद्र में पद भरे जाएंगे। इसके लिए पात्रों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन 29 अगस्त तक जमा किए जा सकते हैं। साक्षात्कार 30 अगस्त को होगा। इच्छुक उम्मीदवार की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा दो पास तथा सहायिका के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पांवटा साहिब के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पड़े कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे।

पांवटा विकास परियोजना अधिकारी रूपेश तोमर ने बताया कि इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी 23 अगस्त तक उनके कार्यालय रामपुरघाट में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत टटियाना के आंगनबाड़ी केंद्र टटियाना-1 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद भरा जाना है। इसके अलावा ग्राम पंचायत मानपुर देवड़ा के मानपुर-1, ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला डोबरी और भरोग बनेड़ी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र भरोग बनेड़ी में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे।

चौरीधार पंचायत में विकास कार्यों में धांधली की हफ्ते में जांच करे बीडीओ

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

चौरीधार पंचायत में विकास कार्यों में हुई धांधली की जांच बीडीओ करें। एक हफ्ते में जांच पूरी कर मंडी डीसी को रिपोर्ट सौंपे। यह निर्देश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दिए। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर इस मामले की रिपोर्ट उनके कार्यालय को प्रेशित करें। शिक्षा मंत्री सेरी बंगलो में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान चौरीधार पंचायत के विकास कार्यों को लेकर एक शिकायत आई। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने लोगों की मांग पर परिवहन विभाग के अधिकारियों को खालूना और सेरी से महावन के लिए एचआरटीसी बस सेवा बहाल करने के निर्देश दिए। मैहंडी पंचायत के रति राम चौहान ने गांव में पेयजल और सड़क की समस्या रखी, जिस पर शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को 2 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा। कोटलू के कर्मसिंह ने भनेरा-कोटलू सड़क का काम सालों से लंबित होने का मामला उठाया, मंत्री ने लोनिवि के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों के खाली पद भरने की मांग पर उपनिदेशक उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा को स्कूलों का निरीक्षण करने और युक्तिकरण की संभावनाएं तलाश कर उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए। कहा जिस स्कूल में 10 से कम बच्चे होंगे, उसे बंद करने पर विचार किया जाएगा। चौरीधार के अमीचंद ने पंचायत में नवनिर्मित पेयजल योजना की मोटर के बार बार जलने की शिकायत की। इस पर मंत्री ने आईपीएच और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को मौका देखने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री कहा कि मौके पर अमीचंद को भी बुलाएं, उनके सुझावों और व्यावहारिक ज्ञान का लाभ लें। कार्यक्रम में 82 वर्षीय अमीर चंद ने निशानदेही का लंबित मामला उठाया, शिक्षा मंत्री ने इस पर एसडीएम, तहसीलदार और एसएचओ को मौका देख कर मामला निपटाने को कहा।

कुल्लू में की 'वेस्ट टू टेस्ट कैफे' की शुरुआत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

शहर को कूड़े की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल की है। हाल ही में कुल्लू से वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने 'वेस्ट टू टेस्ट' कैफे योजना का शुभारंभ किया। योजना का संचालन नगर परिषद कुल्लू की ओर से किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में यह सचमुच एक अनूठी पहल है और कुल्लु शहर में मोटा कचरा यानि प्लास्टिक, शीशा, गत्ता, लोहा आदि लोगों से प्राप्त कर इसका रिसाइक्लिंग से सदुपयोग हो सकेगा। योजना की विशेषता है कि गरीब व्यक्ति भी घर अथवा अन्य घरों से कबाड़ व कचरा एकत्र कर उसे देने के बाद अच्छे रेस्तरां में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का परिवार सहित आनंद उठा सकेंगे। गोविंद सिंह ठाकुर ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे योजना के तहत अनुपयोगी वस्तुओं अथवा कचरे को सरवरी स्थित मटिरियल रिकवरी सुविधा (एमआरएफ) केंद्र में नगर परिषद को सौंपे। इससे कुल्लू शहर को साफ-सुथरा बनाने में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। योजना की सफलता के बाद इसे साथ लगते उपनगरों में भी क्रियान्वित किया जाएगा। मंत्री ने 15 लोगों को कूपन वितरित किए, जिन्होंने एमआरएफ में कचरा जमा करवाया। उन्होंने नगर परिषद, जिला प्रशासन सभी से अपील की कि वे योजना की शुरूआत अपने घरों से करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बनें। इससे पूर्व नगर परिषद के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने योजना के सफल कार्यान्वयन का मंत्री को आश्वासन दिया। उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि व्यंजनों में कॉफी, सिड्डू, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर एवं परिवार के चार सदस्यों को शानदार डिनर का प्रावधान किया जाएगा। मुफ्त कूपन धारक व्यक्ति को ये व्यंजन कुबेर फॉस्ट फूड, ज्ञानी आइसक्रीम, बुक कैफे और सिटी च्वाइस होटल से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि कॉफी के लिए तीन किलो कांच, आधा किलो प्लास्टिक, दो किलो गत्ता व एक किलो ई-वेस्ट में से कोई एक वस्तु जमा करवानी होगी। बर्गर, सिड्डू व मोमो के लिए चार किलो कांच, एक किलो प्लास्टिक, तीन किलो गत्ता व दो किलो ई-वेस्ट में से कोई एक वस्तु, लंच अथवा सैंडविच के लिए ये वस्तुएं क्रमशरू पांच किलो, डेढ़ किलो, चार किलो व तीन किलो में कोई एक चीज जमा करवानी होगी। इसी प्रकार परिवार सहित रात्रि भोज के लिए 10 किलो कांच अथवा, तीन किलो प्लास्टिक अथवा सात किलो गत्ता अथवा छह किलो ई-कचरा देना होगा। वन मंत्र ने लोगों से पौधरोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत बेटी के जन्म पर पांच पौधे वन विभाग की ओर से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जब बेटी पांच वर्ष की हो जाए और पौधे ठीक रहे तो बेटी के नाम पर सरकार पांच हजार रुपये की राशि जमा करवाएगी।

आईआईटी मंडी में हुए घोटाले पर विजिलेंस से मांगा जवाब

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

आईआईटी मंडी में हुए घोटाले का अब भंडाफोड़ होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने आईआईटी मंडी के सेंटर विजिलेंस ऑफिसर से इस बारे में 30 दिनों में मांगा जवाब मांगा है। मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा ने 29 जुलाई को संसद में यह मामला उठाया। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय जागा और कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ाए। इससे पहले भी सांसद ने 31 जुलाई और 9 अगस्त 2018 को भी इस मामले को संसद में उठाया था लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आईआईटी मंडी पर चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। यहां नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई हैं। आईआईटी ने नियमों के विपरीत एक निजी स्कूल को संचालित करने के लिए अपनी करोड़ों की इमारत दे रखी है। आईआईटी परिसर में सिर्फ केंद्रीय विद्यालय ही संचालित किया जा सकता है। इन सभी का खुलासा संस्थान के ही पूर्व कर्मचारी सुजीत स्वामी ने मई 2018 में किया था। सुजीत ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और मुख्यमंत्री तक को इसकी शिकायतें भेजी थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि सुजीत स्वामी ने मंडी में धरना-प्रदर्शन भी किया। विरोध स्वरूप अपने बाल तक मुंडवाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एमएचआरडी ने इन शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की है और आईआईटी मंडी के सीवीओ यानी सेंटर विजिलेंस ऑफिसर से पूरे दस्तावेजों के साथ जवाब मांगा है। सुजीत स्वामी ने उम्मीद जताई है कि एमएचआरडी पूरे मामले की सही और निष्पक्ष ढंग से जांच करके दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। बता दें कि इस मामले को लेकर सुजीत स्वामी सहित अन्य लोगों ने हिमाचल हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की है और हाईकोर्ट ने भी आईआईटी मंडी से चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

सामार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अनुच्छेद 356

भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 को अगर सीधे-सरल भाषा में परिभाषित करें तो इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है । आर्टिकल 356 के लागू होने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाती है और मंत्रीमंडल समूह भी कोई काम नहीं कर सकता है । हालांकि इस आर्टिकल का हमारे देश में उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हुआ है. केन्द्र में विराजमान सरकारें समय-समय पर विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल करती हैं।

राष्ट्रपति शासन (आर्टिकल 356) लगाने की शर्तें...

- राज्य की विधानसभा अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाती
- गठबंधन का ढह जाना
- एसेंबली में बहुमत का न होना
- किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चुनाव का न हो पाना
- 90 के दशक तक ऐसा अक्सर देखा जाता था कि केन्द्र की सरकारें राज्यपाल की मदद से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती थीं। हालांकि सन् 1994 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद इसका अनुचित इस्तेमाल कम हो गया ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 21

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

भारत का संविधान अपने दृष्टिकोण और प्रस्तुति में उपन्यास है। भारत के विशाल और विविध देश होने के नाते, कई पहलुओं और मुद्दों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में इसके नागरिक सबसे महत्वपूर्ण हैं और यह कानून बनाने वालों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कानून किसी भी वर्गीकरण जैसे जाति, रंग या पंथ के प्रत्येक व्यक्ति की समान रूप से रक्षा करता है।

भारत का संविधान भाग III में जीवन का अधिकार (राइट टू लाइफ) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा

दिया गया है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।

'राइट टू लाइफ' क्या है?

अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का प्रतीक है, वह अधिकार है जिससे अन्य सभी अधिकार निकलते हैं। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के बिना, अन्य सभी मौलिक अधिकार बिल्कुल निरर्थक होंगे।

जब हम अनुच्छेद 21 के अर्थ और निहितार्थों का विश्लेषण करते हैं, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं कि यह दो अलग-अलग अधिकारों का प्रतीक है जो वास्तव में अविभाज्य हैं और साथ-साथ चलते हैं। ये दो अधिकार हैं, 1) जीवन का अधिकार, और 2) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

अनुच्छेद 21 के तहत उल्लिखित जीवन 'केवल जीने या सांस लेने की शारीरिक क्रिया को नहीं दर्शाता है। भारतीय संविधान में इसका और भी गहरा अर्थ है जो इसके साथ और भी कई अधिकारों को जोड़ता है, जैसेः

- मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार
- आजीविका का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार
- प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार
- गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार
- विदेश जाने का अधिकार
- एकान्तता का अधिकार
- एकान्त कारावास के खिलाफ अधिकार
- विलंबित निष्पादन के खिलाफ अधिकार
- आश्रय का अधिकार
- हिरासत में मृत्यु के खिलाफ अधिकार
- सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार तथा

कुछ भी और सब कुछ जो एक गरिमापूर्ण जीवन के मापदंड को पूरा करता है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

मां का दूध क्यों जरुरी है नवजात शिशु के लिए

आपको बताते हैं माँ का दूध क्यों जरूरी है नवजात शिशु के लिए। शिशु के जन्म के पश्चात स्तनपान एक स्वाभाविक क्रिया है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव के कारण बच्चों में कुपोषण एवं संक्रमण जैसे रोग हो जाते है। स्तनपान की प्रक्रिया शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करता है।

माँ का दूध बच्चे के लिए केवल पोषण ही नहीं बल्कि जीवन की अमृत धारा है । इससे मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर की सलाहनुसार शिशुओं को जन्म के पश्चात छः महीने तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है।

स्तनपान के प्रति प्रोत्साहन और जन जागरूकता लाने के कारण अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।

बाल्यकाल में होने वाली निमोनिया बीमारी को रोकने में माँ का दूध बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। विश्व भर में सबसे अधिक बच्चों की मृत्यु का कारण निमोनिया है। आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 1.6 करोड़ बच्चों की मृत्यु निमोनिया रोग से हो जाती है। इन आकड़ों की श्रेणी में अधिकांश विकासशील देश है। भारत वर्ष में प्रति वर्ष लगभग 40,000 से अधिक 5 वर्ष से कम के आयु के बच्चों की मृत्यु निमोनिया रोग से होती है।

केवल स्तनपान ही बच्चों को अनेक प्रकार के रोगों से विशेषकर निमोनिया से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकता है। माँ का दूध ही शिशु को अनेक पोषक तत्व देता है साथ ही इम्यूनोग्लोबिन, प्रतिरोधक तत्व भी प्रदान करता है।

इन तत्वों से शिशुओं को श्वसन संबंधित रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है तथा इनके द्वारा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है ।

माँ का दूध सर्वोतम आहार क्यों है

माँ के दूध में सभी तरह के जरूरी पोषक तत्व जैसेः एंटी बाडीज, हार्मोन, प्रतिरोधक कारक और ऐसे आक्सीडेंट पूर्ण रूप से मौजूद होते हैं, जो नवजात शिशु के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है।

जन्म के पश्चात छः माह तक शिशु को माँ के दूध के सिवाय पानी का कोई ठोस या तरल आहार नहीं देना चाहिए क्योंकि माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पानी होता है। इससे छः माह तक के बच्चे को हर मौसम में पानी की पूर्ति माँ के दूध से ही हो जाती है।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: hem.raj@iirdshimla.org

सही करियर का चुनाव कैसे करें

हर कोई जब करियर के चुनाव के पड़ाव में आता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि करियर का चुनाव कैसे करें ? हर कोई अलग- अगल समय पर करियर विकल्प के बारे में सोचता है। ज्यादातर लोग कहलेज ख़त्म होते ही करियर कैसे बनाये के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते है जो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बस पैसे कमाने के लिए वो उस जॉब को कर रहे हैं। करियर का मतलब होता है जिस काम को करने में आपका मन लगे। साथ ही जिस काम से कभी आपका मन न उतरे और रोज उस काम को करने का उत्साह रहे। उस काम में करियर बनाया जाएं तो बात ही कुछ और हो जाएगी। लेकिन दुनिया की भाग दौड़ में हर कोई पैसे कमाने में लगा है। इसलिए सही करियर मार्गदर्शन करना जरुरी है। यहां से आप अपना करियर कैसे बनाये और करियर गाइडेंस इन हिंदी सवाल का जवाब यहां ढूढ़ सकते हैं।

अपने शौक के बारे में विचार करें

जरुरी नहीं की डॉक्टर या इंजीनियर बनने को ही अच्छा करियर कहा जाएगा। करियर उसे कहा जाता है जिस काम को करने में आपके मन को शांति मिले। और मन को शांति सिर्फ उसी काम से मिलेगी जिस काम को आप पंसद करते हैं। इसलिए करियर के चुनाव के लिए आप सबसे पहले अपने शौक यानि की हॉबीज के बारे में सोचें। कई लोग अपने शोक से ही अपना करियर बनाने के तरीके ढूंढ लेते हैं। और उसमें वो लोग काफी सफलता भी प्राप्त करते हैं।

जैसे कि अगर आपको एग्रीकल्चर में शौक है तो आप इसमें भी करियर बनाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। आपको पेंटिंग करने का शौक है तो आप अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिविटी में अच्छे हैं तो आपके पास करियर बनाने के अनगिनत करियर विकल्प हैं। जैसे कि आप इंटिरियर डिजाइनर का करियर विकल्प चुन सकते हैं। या फिर इवेंट मैनेजमेंट का भी आपके पास एक अच्छा करियर मार्गदर्शन है। इससे आप अपने शोक से भी जुड़े रहेंगे और अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी।

सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है। और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है।

प्रोफेशनल लोगों से बात करें

अगर आपके पास कई करियर विकल्प हैं। और आप अपने लिए सही करियर विकल्प नहीं चुन पा रहे हैं। इस समस्या में आप किसी प्रोफेशनल इंसान से बात कर सकते हैं। जो करियर गाइड बनकर आपकी मदद कर सकते हैं। उन लोगों से आप खुद जाकर मिलें। और उनके साथ करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं या फिर फोन पर भी बात कर सकते हैं। आप उन लोगों से अपने करियर मार्गदर्शन के बारे में पूछ सकते हैं। इससे आपको उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा। और उस करियर की अच्छाई और बुराई दोनों पता चलेंगी ।

करियर को चुनते समय इन बातों का भी रखें ध्यान

अगर आप करियर के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। और काफी समय से समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें ? उस समय लगता है कि कुछ भी काम मिल जाए तो हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इस समय ऐसा सोचना ज़ाहिर सी बात है। लेकिन यह करियर मार्गदर्शन का फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सही चीजों को आने में थोड़ा समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी ऑप्शन के लिए सेटल हो जाएं। चाहे थोड़ा समय लगे लेकिन आप वही करियर चुने जिसमें आप अपने आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए सही करियर और सही वक्त का इंतजार करें।

असंभव कुछ भी नहीं है करियर को बदल सकते हैं

कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी खासी नौकरी करने के बाद भी खुश नहीं होते हैं। क्योंकि वो लोग अपने पसंद का काम नहीं कर रहे होते हैं। और उनको लगता है कि अब यही उनका करियर मार्गदर्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपना करियर बदल सकते हैं। कोई भी किसी भी करियर को बदल सकता है। हमने ऐसी सच्ची कहानियां भी सुनी हैं जहां बड़ी कंपनी की जॉब छोड़कर लोग अपने दूसरे करियर के चुनाव को बदल लेते हैं। क्योंकि अपनी पसंद से काम करने का मजा ही कुछ और होता है। और सबसे बड़ी बात इस काम को करने में मन की शांति मिलती है।

डर को कहो बाय-बाय

सबको एक बड़ा घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस चाहिए होता है। लेकिन उसे पहले यह जरुरी होता है कि यह सब किस करियर के चुनाव से मिल रहा है। और कहां से आ रहा है। क्या जो हम काम कर रहे हैं उस काम से खुश हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो सबसे पहले आपको अपने सही करियर के बारे में समझना होगा। और यह बात आपको आपके अलावा कोई नहीं समझा सकता है। इस फैसले को लेने के लिए आपको अपने डर को भगाना होगा । यानि की उसे बाय-बाय बोलना होगा । डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे या फिर कम पैसों में गुजारा कैसे होगा । जिस दिन आप इस डर को निकाल देंगे । उस दिन आप अपने सपनों को पाने की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे।

प्राथमिकता का रखें ध्यान

करियर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखें । जैसे कि जो लोग अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं । उन लोगों को वो करियर नहीं चुनना चाहिए जिसमें उन्हें घर से दूर जाना पड़े । जो लोग घर से दूर रहने के बाद अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनका घर से दूर रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए करियर को चुनते समय अपनी प्रायरिटीज का भी ध्यान रखें। जिससे आपके करियर पर किसी और चीज का प्रभाव न पड़े। और आप अपने करियर पर अच्छे से ध्यान दे सकें। और उसमें सफलता प्राप्त करें।

MISSION RIEV AND VILLAGE EMPOWERMENT

With the objective to create "Ease of Living" for the people by taking up individual concerns, Mission RIEV is an experiment towards bringing happiness on the faces of the people. This innovative approach is supplementary to the endeavors of the government which largely focuses on the infrastructure for public use besides creating provision for regulating various aspects of lifestyle. Here the role of the Mission RIEV is crucial not only in helping people taking advantages of the various schemes and facilities offered by the government but also beyond; to personalize the need of individuals and integrating solutions from various corners. This experiment is going to increase level of satisfaction of the people in the villages as the individual worries and stress will be shared by the Mission with feasible and customized solution within least timeline and cost.

The other part of Mission RIEV is to strengthen the local self-governance in the states of intervention through Gram Sabha mobilization, brining transparency and accountability amongst functionaries and elected representatives through promotion of social audit and giving exposer to various Best Practices taking across country, etc.

These are a few initiatives where Mission RIEV plans to work in close coordination with the Gram Panchayat.

Apart from this contributing in Integrated Risk Management (IRM) is also one of the priority mandates of the Mission specifically to mobilize communities towards Disaster Risk Reduction. Team of dedicated youths shall be there in each Gram Panchayat equipped with basic tools and trainings to perform as First Response Force in any disaster or emergency like situation. This may help in saving many lives especially in the state like Himachal where more than 1000 people lose their lives due to road accidents on annual basis. The immediate rescue from the local people having basic training, may be helpful in reducing the impact of the disaster.

Another area is of afforestation and water conservations. The community needs to come forward to safeguard the forest wealth besides promoting more greenery in order to preserve soil and thereby water. No drop of water can be saved until the top fertile soil is preserved.

Cleanliness is another area of concern which needs collective action. Mission RIEV with the local people and Gram Panchayats shall work in this area and bring the feeling of the landscapes like those in Europe especially in Switzerland.

All these actions are voluntary actions and the **Advisory Bodies at Gram Panchayat, Block, District and State** are mandated with this role. The process of formation of Advisory Boards at different levels is an ongoing process and open for all until things in place everywhere.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

FORMATION OF ADVISORY BOARDS UNDER MISSION RIEV

Background: Mission RIEV is a collaborative flagship programme under the aegis of IIRD which focuses on facilitating people in various affairs impacting progress of the life and thereby making people worry free. The process starts with enrolment of families as members followed by holistic needs assessment and service delivery through the Service Associates deployed from the native panchayats.

As the objective of the Mission is to serve the people, the structure of the Mission mandates transfer the ownership of its affairs to the communities in shape of Advisory Boards at different levels viz. Gram Panchayat, Block, District and State Level.

Tenure: The tenure of the Advisory Boards shall be three year; however the members of Advisory Board shall be eligible for re-consideration. The Mission RIEV management may recommend minimum 60% of the total number of the Advisory Board Members at its discretion and rest 40% can be opted through recommendation of the all types of members. The composition of the Advisory Boards shall be notified annually in case there is change in the names of annual and / or voluntary members.

Removal: Any one not found contributing meaningfully for promotion of the RIEV Services for common good of people or found working detrimental to the image and objectives of the Mission shall be liable to be removed the names from the list of the Advisory Boards. And the Governing Council Mission RIEV shall stand empowered to do so without assigning any reasons.

Roles & Responsibilities: The Advisory Board shall have the following roles and responsibilities:

- To act as Guardian of the Mission within Board and keep on mentoring the affairs of the Mission RIEV functionaries within the concerned.
- To work for sustaining the existing and new services of the Mission and strategise for effectiveness of service delivery mechanism.
- To select the services as per geographical needs of the concerned and take care of the growth of the Service Associates.
- To recommend and approve financial services to the villagers as per prevailing policies of the upcoming / proposed financial institution envisioning home based banking within policy framework of the Mission.
- To promote and work for achieving Sustainable Developmental Goals (SDGs) within the jurisdiction as mandated by Mission and support governmental initiatives.
- To promote Integrated Risk Management (IRM) – Disaster Risk Reduction, Balancing Sustainable Eco-system and Climate Change. Also to perform as First Response Force in case of any disaster like situations. Also take active part in collective actions especially on afforestation, cleanliness and water conservation.

Privileges: Being privileged Ambassadors of the Mission, the Board shall:

- Be facilitated with the Business Cards by the Mission.
- Be offered an honorarium for participating in the quarterly meeting within area.
- Be reimbursed the minimum travel expenses to outstation meetings, if any, by the Mission as per available public transport.
- Have options to avail the food & stay facility at Mission Secretariat Shimla sat subsidised prices whenever visiting and wishing to stay in Shimla subject to availability of the accommodation viz. rooms, dormitory, etc.
- Have the facility to get latest updates on Mission Services through SMS.
- Have the privilege to display their details viz. pictures, contact number and emails, etc. in the Mission's website to be linked to global initiatives.
- Get opportunities to undergo capacity building programmes especially on Integrated Risk Management (IRM) and undertake regional disaster preparedness planning and execution.
- Get its activities published in the Mission's website periodically. Also in the The Riev Times Newspaper.

Advisory Board at Panchayat Level

As the Gram Panchayats are the first level of local self-governance, the direct interaction with the people to know their worries and offer solution takes place at this level only. Hence, the Advisory Board at this level is of great significance.

Composition: There shall be total 11 members in the Panchayat Advisory Board (PAB) comprising of elected representatives, superannuated government officers, social workers, CBO functionaries and intellectuals.

Nature of the PAB: Undertaking roles as part of the PAB shall be a social service opted voluntarily by the members as part of their obligation towards the society.

Eligibility: Only Life Time Members (LTM) shall have the privilege to become the part of the PAB. However, the Governing Council Mission RIEV can also opt Annual and Voluntary Members as Primary Member of the PAB on annual basis.

Process: On the call of the Mission, the interested individual may apply online or offline on the prescribed form for becoming the part of the PAB. The Mission may also nominate some interested individuals based on the recommendations of the members and others. Upon confirmation of the Mission RIEV Governing Council, the PABs shall be notified and details posted in the website.

Meeting: The PAB shall initially meet on quarterly basis or as be notified and the nominated Panchayat Facilitator / Service Associate shall be the nodal functionary.

Privileges: Being privileged Ambassadors of the Mission, the PAB shall:

Be offered an honorarium of Rs. 500/- only for participating in the quarterly meeting within Gram Panchayat.

Advisory Board at Block Level

The primary role of Block Advisory Boards shall be of controlling the service delivery mechanism as the Prog. Officers under Mission RIEV at Block level shall be accountable for ensuring service delivery to the members and the support of the BAB shall be crucial.

Composition: There shall be total 25 members in the Block Advisory Board (BAB) comprising of elected representatives i.e Gram Panchayat Pradhans within Block, superannuated government officers, social workers, CBO functionaries and intellectuals.

Nature of the BAB: Undertaking roles as part of the BAB shall be a social service opted voluntarily by the members as part of their obligation towards the society.

Eligibility: Only Life Time Members (LTM) shall have the privilege to become the part of the BAB. However, the Governing Council Mission RIEV can also opt Annual and Voluntary Members as Primary Member of the PAB on annual basis.

Process: On the call of the Mission, the interested individual may apply online or offline on the prescribed form for becoming the part of the BAB. The Mission may also nominate some interested individuals based on the recommendations of the members and others. Upon confirmation of the Mission RIEV Governing Council, the BABs shall be notified and details posted in the website.

Meeting: The BAB shall initially meet on quarterly basis or as be notified and the nominated Programme Officer -cum- Block Coordinator shall be the nodal functionary.

Privileges: Being privileged Ambassadors of the Mission, the BAB shall:

- Be offered an honorarium of Rs. 1000/- only for participating in the quarterly meeting within Gram Panchayat.

Advisory Board at District Level

The District Advisory Boards shall have the privilege to regulate the RIEV services within the district in light of the district specific problems and priorities while resource planning.

Composition: There shall be total 35 members in the District Advisory Board (DAB) comprising of elected representatives i.e. Panchayat Samiti Chairpersons within District, superannuated government officers, social workers, NGO functionaries and intellectuals.

Nature of the DAB: Undertaking roles as part of the DAB shall be a social service opted voluntarily by the members as part of their obligation towards the society.

Eligibility: Only Life Time Members (LTM) shall have the privilege to become the part of the DAB. However, the Governing Council Mission RIEV can also opt Annual and Voluntary Members as Primary Member of the DAB on annual basis.

Process: On the call of the Mission, the interested individual may apply online or offline on the prescribed form for becoming the part of the DAB. The Mission may also nominate some interested individuals based on the recommendations of the members and others. Upon confirmation of the Mission RIEV Governing Council, the DABs shall be notified and details posted in the website.

Meeting: The DAB shall initially meet on quarterly basis or as be notified and the nominated Programme Manager -cum- District Coordinator shall be the nodal functionary.

Privileges: Being privileged Ambassadors of the Mission, the DAB shall:

Be offered an honorarium of Rs. 1500/- only for participating in the quarterly meeting within Gram Panchayat.

Advisory Board at State Level

The State Advisory Board shall have the privilege to regulate the RIEV services within the state in light of the state specific problems and priorities while resource planning.

Composition: There shall be total 45 members in the State Advisory Board (SAB) comprising of elected representatives i.e. Zila Parishad Chairpersons within State, superannuated government officers, social workers, NGO functionaries and intellectuals.

Nature of the SAB: Undertaking roles as part of the SAB shall be a social service opted voluntarily by the members as part of their obligation towards the society.

Eligibility: Only Life Time Members (LTM) shall have the privilege to become the part of the SAB. However, the Governing Council Mission RIEV can also opt Annual and Voluntary Members as Primary Member of the SAB on annual basis.

Process: On call of the Mission, the interested individual may apply online or offline on the prescribed form for becoming the part of the SAB. The Mission may also nominate some interested individuals based on the recommendations of the members and others. Upon confirmation of the Mission RIEV Governing Council, the SABs shall be notified and details posted in the website.

Meeting: The SAB shall initially meet on quarterly basis or as be notified and the CEO / COO Mission RIEV shall be the nodal functionary.

Privileges: Being privileged Ambassadors of the Mission, the SAB shall:

Be offered an honorarium of Rs. 2000/- only for participating in the quarterly meeting either at Mission Secretariat or anywhere is the State.

370 को निगल गया 56 इंच का सीना

न रहा बांस, न बजेगी बांसुरी

जम्मू कश्मीर पर आज़ादी के बाद ऐतिहासिक निर्णय

केन्द्र सरकार मोदी नेतृत्व में 70 दिनों के शासन में समस्याओं को टालने और पालने से परहेज़ करते हुए समाधान निकालने में अव्वल साबित हुई और आज़ादी के बाद आज तक जो कोई भी सरकार नहीं कर पाई, उस गंभीर विषय पर दोनों हाथों से हथौड़ा चला दिया गया। 'एक भारत, एक संविधान, एक निशान' को सार्थक करते हुए मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 का लगभग सफाया करते हुए राज्य का का विलय भी केन्द्र शासित राज्यों में कर दिया। अब जम्मू-कश्मीर विधानपालिका सहित केन्द्र प्रशासित राज्य होगा जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तरह केन्द्रशासित राज्य होगा।

कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में भारी तादात में सेना की तैनाती और गहमागहमी के बीच अलगाववादियों और कश्मीर के तथाकथित शुभचिंतकों की धड़कने बढ़ती जा रही थी। इन आशंकाओं पर विराम लगाते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जैसे ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने की बात की तो देश भर में तो दिन में ही दीवाली सा उत्सव हो गया जबकि कईयों के माथे पर तेवर के साथ पसीने भी पड़ गए। बड़ी चतुराई से राज्यसभा में बिल को पास करवाकर लोकसभा से भी पारित कर दिया गया तथा बिना देरी किए राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना भी जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री की एक विशेषता तो रही ही है कि सबको दुविधा में रखते हुए निर्णय से सबको चौंका देते हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद अनुच्छेद 370 पर भी करारा प्रहार करते हुए सभी को चौंका दिया। यह ऐसा निर्णय था जिसकी प्रतीक्षा पूरा देश बरसों से कर रहा था और सरकार की प्राथमिकताओं में भी बहुत पहले से इस समाहित किया गया था।

370 का राजनीतिक विश्लेषण

- अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर में संविधान की धारा 356 लागु नहीं होती थी।
- 370 के कारण कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी यानि वहां के नागरिक कश्मीर और भारत दोनों में भिन्न नागरिकता रखते थे।

- कोई भी महिला अगर जम्मू-कश्मीर से बाहर देश के किसी अन्य राज्य में विवाह कर लेती थी तो उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाती थी, इसके उलट यदि महिला पाकिस्तान में विवाह कर ले तो उसकी जम्मू-कश्मीर में नागरिकता बनी रहती है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जम्मू-कश्मीर में लागु नहीं होते थे।
- विधानसभा का कार्यकाल अन्य राज्यों की तुलना में एक वर्ष अधिक होता था यानि 6 वर्ष के लिए।
- जे एंड के का अलग ध्वज होता था तथा भारत के ध्वज की संहिता को वहां के नागरिकों को मानने की प्रतिबद्धता नहीं थी।
- 370 के कारण कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी वहां की नागरिकता मिल जाती थी।
- जे एंड के में 370 के कारण आरटीआई और कैग जैसे कानून लागु नहीं होते थे।
- इसी कारण कश्मीर में पंचायतों को अधिकार प्राप्त नहीं है।

इस प्रकार की अनेक बाधाऐं जम्मू और कश्मीर को देश से अलग करती थी और यह मुख्यधारा में नहीं था। आज जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद और देशद्रोह की निरंतर बह रही ब्यार का कारण यही 370 और 35ए है जिसने इसको देश की मुख्यधारा से अलग कर रखा था।

यहां यह भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि कश्मीर के नागरिकों के साथ अन्याय किया गया और ये सवाल तथाकथित मीडिया में छुटपुट तरीके से उठाए भी गए साथ ही कश्मीर समस्या को वोट और रोटी की नज़र से देखते हुए कुछ तथाकथित नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया। ऐसा मंज़र हमारे देश में ही मिलता है जहां किसी निर्णय पर एक ओर उत्सव का माहौल हो और दूसरी ओर उसी पर कुछ लोग सड़कों पर मातम मना रहे हो।

सबसे मुखर रुप में कांग्रेस ने सरकार को कश्मीर का मर्डर करने वाला बताया। कांग्रेस ने इसका विरोध, वह जिस हद तक कर सकती थी, किया भी। लगा जैसे चोट 370 या 35ए पर नहीं सीधा विपक्षी पार्टी पर कर दी हो। फिर वहीं चिफलन वाले ब्यान और मर्यादाओं का चीरहरण करते हुए विरोध हुआ। कुछ अन्य विरोधी दलों ने भी आग में घी का काम किया और खुद को सूर्खियों में रखने के लिए अनाप-शनाप ब्यानबाजी चलती रही।

जम्मू-कश्मीर पर सियासत के ओले

यहां यह उल्लेख करते हुए ग़लत नहीं होगा कि एक देश में दो-दो कानून हो और इसे सहर्ष ही स्वीकार किया जा रहा था। कश्मीर को लेकर भारत के ही नहीं दुनिया के लोगों को भी हैरानी होती थी। कश्मीर में समस्या की जड़ ही अनुच्छेद 370 थी। 1947 में एक भूल जिसे कहा गया कि समय के साथ-साथ यह घिसती जाएगी और एक दिन ख़त्म हो जाऐगी। लेकिन ये तो नहीं घिसी अलबत्ता इसको हटाने वाले घिसते गए और एक समय में तो लगा कि जम्मु-कश्मीर पर भारत का अधिकार क्या सिर्फ भाषणों तक सीमित है। आज भारत में विश्वस्तरीय नेतृत्व की छवि गढ़ते जा रहे प्रधानमंत्री का शासन है। इसके बावजूद कश्मीर में पिछले कुछ समय से फ़ारुख़ अबदुल्ला और महबूबा की केमिस्ट्री और उनके कांधे से कांधा मिलाते कश्मीर के दुश्मन अलगाववादियों की क़दमताल ने वहां का माहौल ही बिगाड़ कर रख दिया है। मांग उठी कि कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा। यह अपनेआप में पूरे देश का अपमान था। कश्मीर में इन चाटुकारों की सियासत का नमूना तो पूरा देश गाहेबगाहे देखता ही रहता है साथ ही उनकी कार्यप्रणाली पर भी राष्ट्रद्रोह की बू आती है। कश्मीर में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो उनके अपने ध्वज के पीछे ही फहराया जाता रहा है और उसका सम्मान करने की कोई बाध्यता नहीं थी वहां के नागरिकों को। ये कौन सा और कैसा अभिन्न अंग हुआ भारत का ? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं तो इसमें कैसी एकता और अखंडता का गुणगाान ? इसी 370 और 35ए की आड़ में कश्मीर को ज़न्नत से ज़हन्नुम बना दिया गया। कोई प्रश्न नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई उत्तरदायित्व की भावना कश्मीर में दूर-दूर तक नहीं। बस भारत का एक लक्ष्य की इस राज्य को पाले-पोसे और वहां झंडे फहराए जाऐं पाकिस्तान के। इस बेशर्मी के लिए कौन जिम्मेवार रहा, यह बड़ा प्रश्न हो सकता है परन्तु समाधान के लिए आज तक के प्रयासों को नोच डाला गया। जब-जब कश्मीर में सुधार की बात होती, वहां के आला और मौकापरस्त पाकिस्तान के साथ जाने या कश्मीर को आग में झुलसाने की धमकी के साथ अपनी ही थाली में छेद करने से भी बाज नहीं आते। इसे विडंबना ही कहा जाऐगा कि कश्मीर में आम चुनावों में जिस तरीके से चुनाव होते रहे हैं और जिस प्रकार संविधान का मज़ाक बनाया जाता रहा है उससे अब हर ओर नाराज़गी थी।

युवाओं को देश की मुख्यधारा से अलग करके अलगाववादियों ने उनके हाथों में पत्थर थमा दिए और देश की सुरक्षा को ठेंगा दिखाते रहे। ये नौजवान पचास रुपये में एक पत्थर मारकर रोजगार की गारंटी के साथ देश की अस्मिता पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। ये भटके हुए नौजवान ये भी भूल रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में लगे फौजी उन्हीं की हिफाज़त में मुस्तैद है। ये समस्या इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि 370 की आड़ लेकर इन तथाकथित कश्मीरी नेताओं और अलगववादियों ने अपनी सियासी ज़मीन पक्की की और यहां के लोगों को सस्ता राशन और छोटी-मोटी सुविधाओं को लालच देकर भटकाए रखा। पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर बैठ कर इतना आश्वस्त होकर कश्मीर पर चुटकियां लेता रहा है क्योंकि गद्दार घर में ही छिपे हैं।

एक देश एक कानून : समान अधिकारों का देश

जम्मू-कश्मीर में दो भाग करने के बाद अब सारा का सारा परिदृश्य ही बदल जाऐगा। कश्मीर पर भारत सरकार का ही कानून लागू होगा जो कि पूरे देश में लागू होता है। अब कश्मीर में छोटे-बड़े उद्योगों को लगाने का रास्ता साफ हो गया जिससे वहां के संसाधनों का उचित उपयोग होगा और रोजगार के लिए बेहतर माहौल बनेगा। कश्मीर में युवाओं के पत्थर को थामने के पीछे बेराजगारी और काम न होना भी एक बड़ा कारण है। अब जब अपने ही घर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तो भटकाव की स्थिति नहीं रहेगी। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को भी अब जड़ से उखाड़ने में सहायता मिलेगी। इस आतंकवाद पर ही कश्मीर में नेताओं की रोटियां सेंकी जा रही थी। स्थानीय लोगों को बंदूक की नोक पर अपने पक्ष में खड़ा करना भी आम बात है। 370 के हटने के बाद और राज्य का दर्ज़ा ख़त्म होने के बाद कश्मीर की स्थानीय जनता हालांकि शांत है लेकिन उनको उकसाने के लिए वहां के राजनैतिक दलों के मुखिया अभी भी अलग देश और पाकिस्तान जाने की धमकी देने की बातें करते हैं। हालांकि गृह मंत्री की तेवर देखकर सबके पसीने छूट गए हैं। कुछ भड़काउ ब्यान वाले नज़रबंद है अैर कुछ अभी फन नहीं उठा पा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल

भारत के औचक निर्णय के बाद सबसे अधिक घबराहट और हड़बड़ाहट पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हुई। इमरान खान से न तो खुलकर तड़पा जा रहा है और न ही खुलकर विरोध ही हो पा रहा है। जितनी भी छटपटाहट दिख रही है उसके पीछे पाकिस्तान के मीडिया और विपक्षी पार्टियों की परेड का हाथ है। क्योंकि यदि भारत के ख़िलाफ रंजिशवश कोई युद्ध जैसी धमकी की बात सीधे करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ज़वाबदेही मुश्किल हो ही जाएगी लेकिन भारत को उकसाना या कोई भी शरारत करना बालाकोट से भी भयानक परिदृश्य को सामने रख देगा..... इसका इल्म है इमरान को। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तो परमाणु युद्ध तक की धमकी दे दी। जब कुछ नहीं बना तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के पास कटोरा लेकर पाकिस्तान कश्मीर के लिए भारत पर कार्यवाही की मांग लेकर पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने पाकिस्तान का साथ तो दे दिया लेकिन उसमें भारत के पक्ष की मज़बूत नींव को नहीं हिला पाया और अधिकतर देश भारत के समर्थन में आ गए। इतना ही नहीं चीन को भी अब मुश्किल हो गयी है क्योंकि भारत के उपभोक्ता बाज़ार और तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था का लोहा अब दुनिया मान रही है। ऐसे में चीन को खुद को इतने बड़े बाज़ार से इस प्रकार पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होने से जो नुकसान होने वाला है, उसका अनुमान लगाना अभी चीन को संभव नहीं। उधर रुस ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भारत का निजी फैसला है और रुस भारत के पक्ष में है। पाकिस्तान के सारे हथियार चूक गए हैं और अब उनके लिए कश्मीर समस्या नहीं बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर यानि पीओके पर भारत की कार्यवाही से डर सता रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि गृहमंत्री ने संसद में पीओके का भारत में संपूर्ण विलय का शंखनाद किया जिससे इमरान की नींद हराम हो गई है।

उधर उच्चतम न्यायालय में सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के निर्णय के ख़िलाफ दायर याचिका को न्यायाधीश ने यह कह कर याचिका दायर करने वाले की फज़ीहत कर दी कि आधे घंटे तक पढ़ने पर भी यह नहीं समझ आता कि आख़िर कहने का क्या प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने हरसंभव कोशिश जारी रखी है कि कश्मीर में युवाओं को भड़काया जाए और फिर से आतंक की चिंगारी को सुलगाया जाए। लेकिन भारतीय सेना न केवल सीमाओं पर आतंक का जवाब तोपों से दे रही है अपितु कश्मीर के लोगों को गले लगा कर उनकी सुरक्षा एवं सहायता में भी मुस्तैदी से तत्पर है। उधर ट्रंप से मोदी की बात में भी अमेरिका पाकिस्तान को स्पष्ट कर चुका है कि मध्यस्तता की उम्मीद अब पाकिस्तान न रखें।

एक देश एक दिशा एक मन

अब समय आ गया है कि हम देश के भीतर ही नहीं बाहर भी अपने सभी मतभेद भुलाकर दलगत राजनीति से उपर उठकर देश हित में लिए गए निर्णयों पर अपनी एकता का परिचय दें। वर्तमान में जो विपक्षी दलों ने 370 अनुच्छेद के समाप्त होने पर व्यवहार दुनिया के सामने रखा, उसका उपहास ही होना है। हमें देशहित के निर्णयों में एकजुटता का परिचय देने की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि विश्व तो हमारी ऊर्जा, शक्ति और वर्चस्व का लोहा मान लें और हम घर के भीतर ही देशहित के मुद्दों पर राजनैतिक कलह का शिकार होते जाऐं। एक देश, दिशां और एक मन से अखंड भारत की ज्योति को प्रज्जवलित करने के लिए तत्पर होने की आवश्यकता है। कश्मीर में ऐतिहासिक निर्णय के बाद सुबह की उज्जवल किरण और एक नए भविष्य का सूत्रपात तो इसी बात से हो गया जब कई दिनों के बाद कर्फ्यु हटा और स्कूल जाते बच्चों ने नए कश्मीर का स्वागत् किया। अनुच्छेद 370 ने 70 वर्षों से निर्मल जल को दलदल बना कर रख दिया था। इसके हटने से अब न रहा बांस और कभी न ही बजेगी बांसुरी...

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

हिमाचल में बारिश-भूस्खलन से भारी तबाही

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में इस बार बरसात कहर बनके बरपा है। 17 और 18 अगस्त को आसमान से बारिष आफत बनकर बरसी और पूरे प्रदेश में भारी तबाही मची। 18 अगस्त को हर तरफ भूस्खलन, बाढ़ से तबाही का मंजर था। प्रदेश में एक पर्यटक, मां-बेटियों और दादा- पोती समेत 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोग बह गए। दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। शिमला में नौ, सोलन में पांच, चंबा में तीन, कुल्लू में दो और बिलासपुर-सिरमौर जिलों में 1-1 लोगों की जान गई है। इसके बाद भी लगातार बारिश से भारी नुकसान हुआ है।

प्रदेश में नौ नेशनल हाईवे समेत 887 से ज्यादा सड़कें बाधित रहीं। कालका-शिमला और पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल ट्रैक मलबा और पेड़ गिरने से ठप रहे। प्रदेश के तीनों एयरपोर्ट गगल, भुंतर और शिमला में हवाई उड़ानें प्रभावित रहीं। प्रदेश में हाईवे समेत सैकड़ों सड़कें कई मीटर तक बह गईं। दर्जनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए। कुल्लू-मनाली, लाहौल और किन्नौर में हजारों देसी-विदेशी सैलानी और बौद्ध भिक्षु फंस गए हैं। बारिश से 100 के करीब घर और गोशालाएं जमींदोज हो गई हैं। इस सीजन में अब तक करीब 190 लोगों की मौत हो चुकी है।

भारी बारिश से शिमला शहर में पांच लोगों की मौत हो गई। इनमें मां और उसकी दो बेटियां शामिल हैं। आरटीओ कार्यालय के पास एक कच्चे मकान पर मलबा आने से तीनों की जान चली गई। भट्ठाकुफर और जुब्बड़हट्टी के समीप भी भूस्खलन से दो लोगों की मौत हो गई। शहर में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। शहर में 50 से ज्यादा वाहन भूस्खलन और पेड़ गिरने से चकनाचूर हो गए। करीब सौ पेड़ कहर बनकर टूटे। शिमला के नारकंडा के कोनथरू गांव में एक मकान पर पेड़ गिरने से दो नेपाल मूल के लोगों की मौत हो गई, पांच अन्य घायल हैं। ठियोग में खड्डे में बहने से महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी लापता है। रोहडू के हाटकोटी में ट्रक पर पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। सोलन जिले के नालागढ़ के मानपुरा के समीप मानकपुर गांव में मकान जमींदोज हो गया। मलबे में दबने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। बीबीएन की सरसा नदी में एक तीन साल की बच्ची बह गई, जिसका शव कड़ी मशक्कत से स्थानीय लोगों ने निकाला। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। बद्दी में दीवार गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। हरिपुर संडोली में भी एक की जान गई है।

हिमाचल प्रदेश में 73वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया

लोक सेवा आयोग में महिलाएं नि:शुल्क कर सकेंगी आवेदन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश में 73वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य, जिला तथा उप-मण्डल स्तर पर समारोहों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ध्वजारोहण, पुलिस, गृह रक्षा, एनसीसी, आईटीबीपी के जवानों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोहों के मुख्य आकर्षण रहे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, गृह रक्षकों, एनसीसी, स्काउटस् एण्ड गाइडस्, एनएसएस के कैडेटों तथा स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन सभी स्वतंत्रता सेनारियों को स्मरण किया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डा. यशवन्त सिंह परमार द्वारा प्रदेश के विकास की ठोस नींव रखने में दिए गए अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने तथा सर्वस्पर्शी विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार और उद्योगीकरण के प्रोत्साहन को विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में निवेशकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित के लिए आगामी 7 व 8 नवम्बर को धर्मशाला में 'राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट' का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 85000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक विभिन्न संभावित निवेशकों के साथ 38000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि 3.57 लाख से भी ज्यादा वरिष्ठ नागरिक 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा प्रदेश में लगभग 5.35 लाख पात्र जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण तथा महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की है, जिसके तहत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 1.09 लाख कनैक्शन वितरित किए गए हैं, जो योजना के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्य से अधिक है। केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत भी प्रदेश में 1.15 लाख कनैक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए नई राहें-नई मंजिलें नाम से नई योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अछूते क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में शिमला की चांशल घाटी, मण्डी की जंजैहली वैली तथा कांगड़ा के बीड़ बिलिंग को विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने निषाद कुमार तथा लैफ्टिनेंट प्रतिभा जम्वाल को हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने सुबेदार रिनजिन दोरजे (मरणोपरांत), अलाईका तथा हिमकारा संगठन को प्रेरणा स्त्रोत पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सिविल सर्विसिज पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा ने प्राप्त किया। राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पुरस्कार कुल्लू तथा लाहौल-स्पिति जिलों को प्रदान किए, जिन्हें क्रमशः उपायुक्त यूनुस खान तथा अश्विनी कुमार ने प्राप्त किया।

जय राम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ते की घोषणा की, जो जनवरी, 2019 से देय होगा। इस निर्णय से प्रदेश के कर्मचारियों को 260 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेंगे।

जल शक्ति अभियान पर गंभीरता से करें कार्य: मुख्य सचिव

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने राज्य सरकार के सभी विभागों से जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण, गांवों में तालाबों एवं टैंकों के रख-रखाव की दिशा में कार्य करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जिलों में जल शक्ति अभियान आरम्भ करने की आवश्यकता है ताकि सही मायनों में जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मुख्य सचिव जल स्त्रोत प्रबन्धन के लिए योजना विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जल संरक्षण से सम्बन्धित जल स्त्रोतों व भू-जल के नवीनीकरण, सहभागी सिंचाई पद्धति डिमांड साईड प्रबंधन, जलापूर्ति व स्वच्छता, वर्षा जल संग्रहण आदि विषयों पर गहन चर्चा की गई।

उन्होंने वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य स्तर पर जल के महत्त्व को समझते हुए सभी विभागों को जल के प्रयोग में अधिक दक्षता लाने के लिए प्रयास करने होंगे। उन्होंने जल संरक्षण के लिए पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले वैज्ञानिक तथा अन्य जानकारी का प्रयोग करने का सुझाव दिया।

मुख्य सचिव ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टीम की तरह कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में 'वाटर स्ट्रैस्ड' जिलों सिरमौर, सोलन, ऊना और कांगड़ा के उपायुक्तों एवं अतिरिक्त उपायुक्तों ने भी वर्षा जल संरक्षण पर किए गए कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तुतियां दी।

राजभवन में 'ऐट होम' का आयोजन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज राजभवन में 'ऐट होम' की मेजबानी की। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, लेडी सत्यावती मिश्र और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रही।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, हि.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधायकगण, चीफ ऑफ स्टाफ आरट्रैक ले. जनरल जी.एस. सांघा, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, पुलिस महानिदेशक एस.आर मरड़ी, उप कुलपति, स्वतंत्रता सेनानी, राज्य सरकार के सिविल, पुलिस तथा सेना के वरिष्ठ अधिकारी, शहर के गणमान्य व्यक्ति तथा भूतपूर्व सैनिक अन्यों सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल भवन, नई दिल्ली में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल भवन, नई दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया धूमधाम से गया। इस अवसर पर उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में आवासीय आयुक्त कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर पूर्व राज्य सभा सदस्य तथा वरिष्ठ भाजपा नेता कृपाल परमार भी उपस्थित थे। इससे पूर्व, लाल किले में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिमाचल पैवेलियन में सांस्कृतिक वेशभूषा में सुसज्जित हिमाचल प्रदेश के कलाकारों तथा सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया।

मनाली में स्थापित होगी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के लोगों ने 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कुल्लू जिला के मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वत्तारोहण एवं सम्बद्ध खेल संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंच सके और उन्होंने शिमला से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'अटल स्मृति-2019' कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी ने राष्ट्र को गतिशील नेतृत्व प्रदान किया और उन्हें विश्व में एक महान् नेता के रूप में पहचान प्राप्त है। जय राम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय उच्च मार्ग विकास परियोजना को आरम्भ किया। ये परियोजनाएं देश और विशेष रूप से हिमाचल के लिए वरदान साबित हुई हैं तथा इन योजनाओं के माध्यम से हजारों गांवों को सड़क सुविधाओं से जोड़ा जा सका है।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से मनाली में स्थापित की जाने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की आधारशिला भी रखी। इस दौरान उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जगतसुख के 2.62 करोड़ रुपये से निर्मित भवन का लोकार्पण किया और 2.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली कृत्रिम रहक क्लाईमिंग वॉल की आधारशिला भी रखी।

एचपी ई-पास पोर्टल बंद, छात्रवृत्ति के लिए अब ऐसे आवेदन कर सकेंगे विद्यार्थी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

करीब 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले से सबक लेते हुए हिमाचल सरकार ने बीते कई सालों से छात्रवृत्ति आवेदनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एचपी ई-पास पोर्टल को बंद कर दिया है। अब केंद्र और राज्य सरकार की 16 विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना होगा।

एक मोबाइल नंबर पर एक ही छात्र का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण होगा। एचपी ई-पास पोर्टल की इस खामी के चलते ही बड़े स्तर पर फर्जी आवेदन हुए हैं। नेशनल पोर्टल पर आवेदन करने से लेकर पैसा जारी होने तक हर गतिविधि का छात्रों को पोर्टल से एसएमएस भेजा जाएगा। ई पास पोर्टल में यह सुविधा नहीं थी। छात्रवृत्ति के पुराने आवेदन भी भारत सरकार के पोर्टल पर रिन्यू करवाना अनिवार्य किया गया है।

एचपी ई-पास पोर्टल से डाटा ट्रांसफर नहीं करने के चलते ऐसा हुआ है। नेशनल पोर्टल पर छात्रों के आधार नंबर से जुड़े बैंक खातों में ही पैसा डाला जाएगा। शिक्षण संस्थानों को भी ऑनलाइन ही आवेदनों का वेरिफाई करना होगा। इस पोर्टल के इस्तेमाल के लिए हिमाचल सरकार को कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। एचपी ई-पास पोर्टल के लिए शिक्षा विभाग को शुल्क चुकाना पड़ता था।

15 और 31 अक्तूबर तक होंगे आवेदन

इस पोर्टल की कई कमियों के चलते ही हिमाचल में 250 करोड़ से अधिक राशि का घोटाला सामने आया है। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए इस साल आवेदन करने को भारत सरकार ने पोर्टल खोल दिया है। कुछ योजनाओं के लिए 15 और कुछ के लिए 31 अक्तूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। निर्धारित तारीख के बाद पोर्टल नहीं खुलेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा के मुताबिक छात्रवृत्ति आवेदन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एचपी ई०पास पोर्टल बंद करने का फैसला लिया गया है।

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा
फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com
Title Code : HPBIL00313
RNI Reference No. 1328500

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

विश्वेश्वर हेगड़े बने कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कर्नाटक में हाल ही में नई सरकार आने के बाद नए स्पीकर (अध्यक्ष) का चुनाव कर लिया गया है। कर्नाटक विधानसभा से स्पीकर के तौर पर केआर रमेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। केआर रमेश कुमार को इस्तीफा देने के बाद विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी को नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने 30 जुलाई 2019 को अपना नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उपस्थित रहे थे। वे अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 राज्य सभा में पारित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया है। सदन में विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने वाली एजेंसियों को चार कदम आगे बढ़कर काम करना होगा तभी आतंकवाद खत्म होगा और इन प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की द्रुत गति से जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना है। विधेयक में विभिन्न प्रस्ताव रखे गये हैं जिनमें संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराध होने पर उनकी तुरंत जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान करना है।

रवीश कुमार को मिला 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को 2019 का प्रतिष्ठित 'रेमन मैग्सेसे' सम्मान हेतु नामित किया गया है। यह सम्मान एशिया में साहसिक एवं परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। रवीश कुमार को यह सम्मान आवाजों की आवाज बनने के लिए तथा हिंदी टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है।

रवीश कुमार हिन्दी न्यूज चौनल एनडीटीवी इंडिया के सबसे प्रमुख चेहरा हैं। रवीश कुमार के अतिरिक्त 2019 का मैग्सेसे अवॉर्ड म्यांमार के को स्वे विन, थाईलैंड के अंगखाना नीलापाइजित, फिलीपीन्स के रेमुन्डो पुजांते तथा दक्षिण कोरिया के किम जोंग-की को भी मिला है।

राज्यसभा ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक-2019 को मंजूरी दी

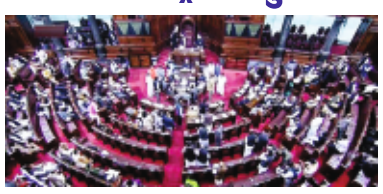

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्यसभा से 01 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक–2019 को मंजूरी मिल गयी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया। इसमें चिकित्सा क्षेत्र एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के नियमन हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह एनएमसी (नेशनल मेडिकल कमीशन) के गठन का प्रस्ताव है। इस विधेयक पर लाए गए विपक्ष के संशोधनों को ध्वनिमत से जबकि दो संशोधन प्रस्तावों को क्रमशः 61 के मुकाबले 106 मतों तथा दूसरे को 51 के मुकाबले 104 मतों से खारिज कर दिया।

लोकसभा ने 29 जुलाई 2019 को 'राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक–2019' को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक संघीय स्वरूप के खिलाफ है।

पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार निलंबित करने की घोषणा की है। पुलवामा हमले के बाद भारत पहले ही पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन चुका है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान ने पाकिस्तान की सुरक्षा समिति के साथ की गई बैठक में यह निर्णय लिया है। पाकिस्तान द्वारा यह घोषणा की गई कि वह भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को समाप्त करने के साथ-साथ मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों पर भी विचार किया जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि, कैबिनेट ने दी मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के बढ़ते बोझ को देखते हुए कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। सीजेआई रंजन गोगोई ने हाल ही में कहा था कि जजों की कमी के कारण कानून के सवालों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला लेने के लिए आवश्यक संवैधानिक पीठों का गठन नहीं किया जा रहा है।

राज्यसभा में पास हुआ मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक – 2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्यसभा में 31 जुलाई 2019 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक–2019 पास हो गया है। यह विधेयक पहले ही 23 जुलाई को लोकसभा में पास हो चुका है। सड़क हादसों को रोकने हेतु नए संशोधित बिल में कई नए प्रावधान किए गए हैं। इस बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और ज्यादा कड़ा किया गया है। नए बिल के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा सकता है। इस बिल में शराब पी कर वाहनों चलाने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान रखे गए हैं।

पृथ्वी शॉ डोपिंग मामले में फंसे, BCCI ने 8 महीने के लिए किया सस्पेंड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को निलंबित कर दिया है। बीसीसीआई ने उन्हें डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के चलते निलंबित किया है। बीसीसीआई ने पृथ्वी शह को आठ महीने के लिए निलंबित किया है। पृथ्वी शॉ ने बीसीसीआई के डोपिंग रोधी परीक्षण कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी 2019 को इंदौर में सैयद मुश्ताक अली ट्राफी के दौरान टेस्ट कराया था। परीक्षण के बाद उनके नमूने में टरबुटैलाइन पाया गया। टरबुटैलाइन वाडा की प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल है। यह पदार्थ आमतौर पर खांसी की दवाई में पाया जाता है।

राष्ट्रपति ने 'तीन तलाक' विधेयक को दी मंजूरी, अब अपराध करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है। इस मंजूरी के साथ ही 'तीन तलाक' कानून अस्तित्व में आ गया है। यह कानून देश में 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा. संसद के दोनों सदनों में 'तीन तलाक' बिल पहले ही पास हो चुका है। तीन तलाक बिल को 'सेलेक्ट कमेटी' के पास भेजने का प्रस्ताव राज्यसभा में वोटिंग के बाद गिर गया था। वोटिंग के दौरान बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां राज्यसभा से वॉकआउट कर गई थीं।

त्रिपुरा से 7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य की शुरुआत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2019 को सातवीं आर्थिक जनगणना त्रिपुरा राज्य से आरंभ की गई है। इसके बाद यह कार्य पुद्दुचेरी में किया जाएगा। इसे अगस्त एवं सितम्बर में अन्य राज्यों में भी आरंभ किया जायेगा। इस जनगणना के लिए आंकड़े जुटाने, उनके प्रमाणीकरण, रिपोर्ट तैयार करने और इनके प्रसार के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन पर आंकड़े एकत्र करने हेतु सीएसएसी द्वारा इस कार्य में लगाए जाने वाले गणनाकारों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

झारखंड के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा झारखंड में 10 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के पहले चरण में राज्य के 15 लाख किसानों को योजना का लाभ दिया जायेगा। उपराष्ट्रपति द्वारा रांची स्थित हरमू मैदान से योजना का शुभारंभ किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्य के मंत्रीगण, सांसद व विधायकगण द्वारा योजना का शुभारंभ कर राज्य का किसानों को लाभान्वित करेंगे। योजना का उद्देश्य झारखंड के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा ऋण के कारण कृषि में समस्या का सामना कर रहे किसानों की मदद करना है।

पाकिस्तान ने 'हमेशा के लिए' समझौता एक्सप्रेस सेवा बंद की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 रद्द करने के बाद पाकिस्तान ने एक और कदम उठाते हुए समझौता एक्सप्रेस रद्द करने की घोषणा की है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जारी इस जानकारी में कहा गया है कि पाकिस्तान ने हमेशा के लिए समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की सेना बंद करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद द्वारा जारी घोषणा में कहा गया है कि समझौता एक्सप्रेस की सेवायें सदैव के लिए बंद कर दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने टिकटें पहले से खरीद रखी हैं वे लाहौर ऑफिस से पैसे वापिस ले सकते हैं।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पैनल गठित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के चयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 12 सदस्यीय एक पैनल गठित किया गया है। इस पैनल में भारत की स्टार बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरी कॉम, बाइचुंग भूटिया भी शामिल हैं। यह खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को दिए जाते हैं, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती भी होती है। इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सभी पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया जा रहा है क्योंकि अलग-अलग पुरस्कारों के लिए ज्यादा समितियां गैर जरुरी हैं, इनसे चीजें मुश्किल होती हैं और विवाद उत्पन्न होते हैं।

भारत रत्न 2019 : प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका सम्मानित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जनसंघ के नेता नाना जी देशमुख एवं प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को 08 अगस्त 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न सम्मान की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को की गई थी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था।

समग्र शिक्षा – जल सुरक्षा अभियान का शुभारंभ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने हाल ही में 'समग्र शिक्षा – जल सुरक्षा' अभियान का शुभारंभ किया।

इस अभियान की शुरुआत दिल्ली कैंट स्थित केन्द्रीय विद्यालय से की गई। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ मिलकर 350 से अधिक पौधों का रोपण किया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए देश के 10 करोड़ से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को साथ जोड़ना है। इस दौरान उपस्थित सभी बच्चों से एक लीटर पानी प्रतिदिन बचाने का संकल्प दिलाया गया।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के लिए पंजीयन शुरु

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के लिए 09 अगस्त 2019 से पंजीयन की शुरूआत हो गई हैं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना से छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर होगा। योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य इस वर्ष हासिल कर लिया गया है। पीएम किसान योजना के तहत अभी तक 5,88,77,194 तथा 3,40,93,837 किसानों को क्रमशः पहली और दूसरी किस्त प्राप्त हुई है।

66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार : आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल बने सर्वश्रेष्ठ कलाकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत सरकार द्वारा 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की 09 अगस्त 2019 को घोषणा की गई। यह पुरस्कार वर्ष 2018 में रिलीज हुई फिल्मों के आधार पर दिया गया है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है लेकिन इस वर्ष लोकसभा चुनावों के कारण यह घोषणा अगस्त में की गई हैं। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आयुष्मान खुराना की फिल्म अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का सम्मान हासिल हुआ है। वहीं इस फिल्म के कलाकार आयुष्मान खुराना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान हासिल हुआ है। उन्हें यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 'उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक' के कलाकार विक्की कौशल के साथ संयुक्त रूप से मिला है। इसके अलावा संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' के 'घूमर' गाने को बेस्ट कोरियोग्राफी का अवॉर्ड मिला है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन में जरुरी सामान की हो जाएगी किल्लत ! लीक रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अगर बिना शर्तो के ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग होता है तो उसे ईंधन, खाद्य पदार्थो और दवाओं की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। यह बात ब्रिटिश सरकार के एक गोपनीय दस्तावेज में कही गई है, जो लीक होकर मीडिया के पास पहुंच गया है। 100 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पत्र लिखकर ब्रेक्जिट के बाद की स्थिति पर विचार के लिए संसद का आपात बैठक बुलाने की मांग की है। इस बीच ब्रेक्जिट प्रक्रिया पर विचार के लिए जहनसन ने यूरोपीय नेताओं से मिलने का निर्णय लिया। 31 अक्टूबर को पूरी होने वाली संबंध विच्छेद की इस प्रक्रिया के बाद ब्रिटेन में बंदरगाहों पर जहाजों का तांता लग सकता है, विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं और अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस आशंका से संबंधित खुफिया रिपोर्ट कैबिनेट कार्यालय के पास पहुंची है। लेकिन ब्रेक्जिट मामले में समन्वय बना रहे मंत्री माइकल गोव ने मीडिया में आई इन बातों का खंडन किया है। कहा कि सबसे बुरी स्थिति के विषय में ये बातें कही गई हैं। जरूरी नहीं है कि यह सब हो। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में 85 प्रतिशत माल ढुलाई का कार्य ट्रकों के जरिये होता है। ब्रेक्जिट के बाद ये ट्रक फ्रांस के सीमा शुल्क विभाग की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए बचे हुए समय में व्यवस्थाओं में सुधार के लिए तत्परता से कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने सरकारी दस्तावेज पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यूरोपीय यूनियन से चल रही वार्ता को प्रभावित करने के लिए एक पूर्व मंत्री ने यह रिपोर्ट लीक कराई है। रविवार को ब्रेक्जिट मामलों के मंत्री स्टीफन बर्कले ने कानूनों में बदलाव के प्रस्ताव तैयार करने के आदेश पर दस्तखत कर दिए। नए कानून 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से अलगाव के बाद लागू होंगे।

चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद पर दिए नरमी के संकेत, जल्द तय हो सकता है नतीजा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बीजिंग में हुई बातचीत के दौरान भले ही यह तय हुआ हो कि सीमा विवाद को 2005 में तय संदर्भों के तहत सुलझाया जाएगा, लेकिन चीन की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि इस विवाद पर अगले दौर की वार्ता किसी ठोस निष्कर्ष की ओर बढ़ सकती है। इन संकेतों की एक वजह भारत की ओर से इसका उल्लेख प्रमुखता से किया जाना है कि इस विवाद का समाधान करके ही दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को पाटा जा सकता है। इसका आभास भारत-चीन मीडिया फोरम में भागीदारी करने आए भारतीय पत्रकारों के दल ने बीजिंग से लेकर शंघाई में हर उपयुक्त मंच पर प्रमुखता से किया। इस दल ने चीनी मीडिया से लेकर चीन सरकार के विभिन्न प्रतिनिधियों के समक्ष इस पर भी जोर दिया कि सीमा विवाद को सुलझाने में जरूरत से ज्यादा देर हो रही है और उसके चलते भारतीय जनता अधीर भी हो रही है और आशंकित भी। चीनी अधिकारियों ने जहां सीमा विवाद पर नरमी के संकेत दिए वहीं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) में भारत की सदस्यता पर अपने पुराने रुख को कायम रखा। भारत - चीन सीमा विवाद को लेकर बीते दो दशकों से अधिक समय से बातचीत जारी है। इस बातचीत के अगले दौर की प्रतीक्षा हो रही है। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के आगामी भारत दौरे के आसपास दोनों पक्ष के प्रतिनिधि सीमा विवाद के अगले दौर की वार्ता के लिए एक - दूसरे के समक्ष होंगे। शी चिनफिंग को वुहान में कायम समझबूझ को आगे बढ़ाने के लिए भारत आना है। सीमा विवाद में प्रगति के आसार इसलिए भी हैं, क्योंकि चीन को यह आभास हो रहा है कि वह इस तर्क को और अधिक नहीं खींच सकता कि आखिर जब उसने म्यांमार, रूस समेत अन्य देशों के साथ अपने सीमा संबंधी विवाद सुलझा लिए हैं तो वह भारत से जुड़े सीमा विवाद को भी विराम देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अब चीन की इस प्रतिबद्धता को पूरा होते हुए देखना चाह रहा है।

भारत ने अनुच्छेद 370 पर साफ किया नजरिया

हालांकि चीन ने जम्मू - कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर आपत्ति जताई है, लेकिन भारत ने पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिये और फिर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया का ध्यान खींचने वाले संबोधन के माध्यम से यह साफ कर दिया है कि वह अपने इस फैसले से टस से मस नहीं होने वाला है। साथ ही चीन को कश्मीर पर चिंता जताने की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाकर किसी नए इलाके पर कोई दावा नहीं किया गया है।

अमेरिका ने सरकारी सुविधाएं चाहने वाले प्रवासियों को ग्रीन कार्ड देने से इनकार किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ट्रंप प्रशासन ने 12 अगस्त 2019 को कानूनी आव्रजकों के अमेरिकी नागरिक बनने की राह को और ज्यादा मुश्किल बनाते हुए कहा कि 'फूड स्टांप' या 'हाउसिंग असिस्टेंस' जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ लेने वालों को ग्रीन कार्ड देने से इनकार किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने अवैध आव्रजन रोकने के यह नए नियम बनाए हैं। नये नियम 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अमेरिका में खाद्यान्न, चिकित्सा, आवास और लोक कल्याण की कई सरकारी योजनाओं का लाभ अमेरिकी निवासियों को मिलता है। नये नियम के तहत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदक की वित्तीय स्थिति, आयु, शिक्षा और उसके अंग्रेजी की जानकारी के स्तर को आधार मानकर फैसला लिया जाएगा। किसी एक मानदंड को आधार मानकर मामले पर विचार मुख्य रूप से नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वैध और अवैध आव्रजन को कम से कम करना चाहते हैं। वह आव्रजन को अमेरिका के हित हेतु इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेक्सिको सीमा पर दीवार का निर्माण भी राष्ट्रपति ट्रंप की इसी नीति का हिस्सा है। वे इसके जरिये मेक्सिको से होने वाली घुसपैठ पर रोक लगाना चाहते हैं।

भारत – भूटान के रिश्तों पर चीन को समस्या

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के साथ भूटान के कूटनीतिक रिश्ते हैं जबकि चीन के साथ उसके इस तरह के रिश्ते भी नहीं हैं। डोकलाम विवाद के समय भी भूटान ने भारत का साथ दिया था। चीन के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा खास मायने रखता है। चीन की कोशिश हमेशा से रही है कि भूटान में उसका प्रभाव बढ़े और कूटनीतिक संबंध बेहतर हों, लेकिन भूटान का साफ रुख यह है कि वो भारत के साथ है। भारत के साथ भूटान के कूटनीतिक रिश्ते हैं, जबकि चीन के साथ उसके इस तरह के रिश्ते भी नहीं हैं। डोकलाम विवाद के समय भी भूटान ने भारत का साथ दिया था।

चीन को खटकती है मैत्री संधि

भारत और भूटान की दोस्ती को और करीब लाने में 1949 में हुई इस संधि का बड़ा योगदान रहा है। इस संधि के तहत भूटान को अपने विदेशी संबंधों के मामले में भारत को भी शामिल करना होता है। लेकिन, 2007 में इस समझौते में संशोधन हुआ और इसमें जोड़ा गया कि जिन विदेशी मामलों में भारत सीधे तौर पर जुड़ा होगा, उन्हीं में भूटान उसे सूचित करेगा। यही नहीं, इस संधि से दोनों देश, अपने राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग करने तथा एक दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के विरुद्ध अपने क्षेत्रों का उपयोग न करने देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इसलिए भारत और भूटान के बीच की यह संधि चीन को हमेशा खटकती रही है।

मजबूत व्यापार संबंध से परेशानी

भारत और चीन के बीच हिमालय की गोद में बसे आठ लाख आबादी वाले देश भूटान की वित्तीय और रक्षा नीति पर भी भारत का प्रभाव है। यही नहीं, भूटान अपना 98 फीसद निर्यात भारत को करता है और करीब 90 फीसद सामान भी भारत से ही आयात करता है। भारतीय सेना भूटान की शाही सेना को प्रशिक्षण देती रही है। ये बातें भी चीन को कहीं न कहीं परेशान करती रही हैं।

सासेक परियोजना ने बढ़ाई चिंता

2001 में भारत ने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश व म्यांमार को जोड़ने के लिए सासेक (साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) कॉरिडोर शुरू किया था। इंफाल से मोरेह (म्यांमार) को जोड़ने वाले इस मार्ग को पूर्वी एशियाई बाजार के लिए भारत का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। भारत की योजना इस मार्ग के जरिये पूर्वी एशियाई बाजारों को पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने की है। इंफाल - मोरेह मार्ग के निर्माण के साथ ही बैंकाक तक पहुंचने के लिए भारत को एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। 2014 में मालदीव और श्रीलंका भी इसके सदस्य बन गए। चीन की महत्वकांक्षी ओबीओआर परियोजना के जवाब में भारत यह परियोजना लेकर आया है

इमरान के नए पाकिस्तान में लोगों को खाने के लाले, ब्रेड, दूध और रोटी भी हुई महंगी

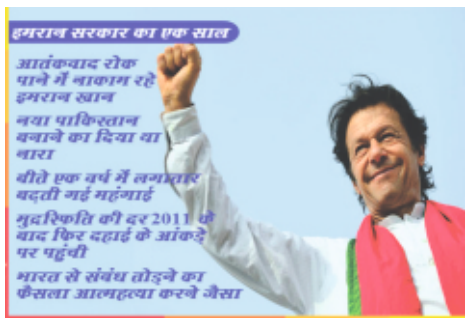

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नया पाकिस्तान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान जब से सत्ता में आए हैं तब से देश की हालत लगातार खराब हो रही है। एक तरफ बेकाबू होती महंगाई तो दूसरी तरफ गैस और तेल के दामों में होती बढ़ोतरी सभी ने आम इंसान की हालत पतली कर रखी है। इस पर भारत से संबंध तोड़ना पाकिस्तान के लिए खुदकुशी करने जैसा कदम रहा है।

पाकिस्तान पर चीन का कर्ज भी इस खराब होती हालत की एक बड़ी वजह है। यही वजह है कि इस बार की ईद भी वहां पर कमोबेश सूनी ही रही है। भारत संबंध तोड़ने के फैसले पर लोगों ने पीएम इमरान खान से यहां तक पूछ डाला कि वह आखिर क्या घास खाएं? पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाने वाली कई सारी चीजें भारत से ही जाती हैं। इनमें टमाटर और प्याज खास हैं। 18 अगस्त 2019 को उनकी सरकार को एक साल पूरा हो गया। इस एक साल के दौरान वह हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। आतंकवाद को रोकने का मसला हो या फिर देश के विकास की बात हो इमरान की सरकार किसी भी मोर्चे पर न तो अपनी आवाम को न ही दुनिया को संतुष्ट कर सकी है। इसका जीता जागता सुबूत एफएटीएफ की वो तलवार है जो पिछले करीब दो वर्ष से पाकिस्तान के ऊपर टंगी हुई है। पाकिस्तान की मीडिया में भी यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि इमरान सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2011 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि देश में मुद्रास्फिति की दर दहाई के आंकड़े को पार कर गई है। इतना ही नहीं सरकार के अपने अनुमान के मुताबिक इसके 11 फीसद तक बढ़ने की उम्मीद की गई है।

पाक मीडिया के मुताबिक सीएनजी, पीएनजी, रुपये में गिरावट, जरूरत की चीजों के दाम और टैक्स में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब ढीली हो रही है। एक डहलर की कीमत बीते एक वर्ष में 35 रुपये तक बढ़ी है। अगस्त 2018 में एक डहलर की कीमत 123 थी वह अब बढ़कर 158 तक पहुंच चुकी है। वहीं पेट्रोल के दाम 95.24 रुपये से बढ़कर 117.84 तक हो चुके हैं और डीजल 112.94 रुपये से बढ़कर 132 रुपये के पार हो चुका है। इमरान सरकार की काबलियत और उनकी विफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब वह सरकार में आए थे तब सीएनजी की कीमत 81.70 रुपये थी जो अब 123 प्रति किग्रा तक पहुंच चुकी है। यह कीमत भी स्थिर नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि यह अभी और बढ़ेगी।

आईएएस लड़ाकों का काल है ये महिला बिग्रेड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत - समेत दुनिया भर में नारी सशक्तिकरण और महिलाओं की बराबरी एक बड़ा मुद्दा है। दुनिया के बहुत से देशों में आज भी महिलाओं को कुछ खतरनाक सेवाओं में पुरुषवादी मानसिकता की वजह से नहीं रखा जाता है। दूसरी तरफ महिला कमांडो का ये दस्ता, आतंकियों के मुख्य गढ़ में उनके दांत खट्टे कर रहा है। इन खूबसूरत योद्धाओं का नाम दुनिया की सबसे खतरनाक योद्धाओं में शामिल है। किसी भी तरह का मुकाबला करने के लिए इन महिला कमांडो को हर तरह के हथियार और गोला - बारूद का प्रशिक्षण दिया गया है। इराक की ये बहादुर कुर्दिश महिलाएं, कुर्दिश पेशमेर्गा फाइटर्स में शामिल हैं। इराक के बर्लिन में इन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। आईएस लड़ाकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुर्द दस्ते की ये लड़कियां उन पर इस कदर भारी पड़ेंगी। इन कुर्द लड़कियों ने चरमपंथियों के दांत खट्टे कर दिए हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन जांबाजों को एक गीत बार - बार सुनाया और याद कराया जाता है, जिसके बोल हैं प्यारी मां, मेरे लिए आंसू मत बहाना। मैं मातृभूमि पर मिटने के लिए तैयार हूं। मैं दुश्मन को मिटाने जा रही हूं। इस गीत का इस्तेमाल इन लड़कियों में देशभक्ति और बलिदान की भावना पैदा करने के लिए किया जाता है। कुर्द, एक विवादास्पद इलाका है, जो इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से तो लड़ रहा है। ईरान, सीरिया और तुर्की सीमावर्ती इलाकों में कुर्द आबादी को अपने लिए खतरा मानते हैं। इन महिलाओं का कहना है कि कुर्दिस्तान एक है। उन्होंने इलाके के सारे कुर्दों की हिफाजत के लिए हथियार उठाए हैं। ईरान से सैन्य ट्रेनिंग के लिए इराक पहुंचने वाली इन कुर्द महिला योद्धाओं की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है। इनमें से ज्यादातर लड़कियों ने विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के लड़ाके इसलिए भी इन महिला योद्धाओं से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यदि इनकी मौत किसी महिला सैनिक के हाथों हुई तो उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। 2017 में आईएस ने इन्हीं कुर्द लड़ाकों में शामिल एक 23 वर्षीय लड़की जोआना पलानी को मारने पर 10 लाख डॉलर का ईनाम रखा था। इस लड़की ने अकेले आईएस के 100 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगाया है। कुर्दिश मूल की डैनिश महिला पलानी ने 2014 में पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद वह आईएस के खिलाफ जंग में उतर गई।

ई-सिगरेट, निकोटिन फ्लेवर वाले हुक्का पर पाबंदी के लिए अध्यादेश ला सकती है केंद्र सरकार

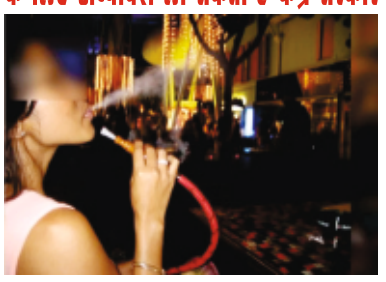

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार ई-सिगरेट समेत इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम्स (ईएनडीएस) उत्पादों के निर्माण, बिक्री और आयात पर पाबंदी लगाने के लिए अध्यादेश ला सकती है। हालांकि सरकार इन पर रोक लगाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है लेकिन यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उठाया जाएगा। कोर्ट पहले अपने एक आदेश में ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले पर रोक लगा चुका है। धूम्रपान के वैकल्पिक उपकरणों जैसे ई-सिगरेट, हीट-नॉट-बर्न डिवाइस, वेप और ई-निकोटिन स्वाद वाले हुक्कों पर पाबंदी लगाना स्वास्थ्य मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 75 दिन पूरे हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ईएनडीएस डिवाइस के निर्माण, बिक्री, वितरण और आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए हरकत में आया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय इस मुद्दे पर कानूनी राय भी ले रहा है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

THE CURRENT AFFAIRS 2019

- हाल ही में सरकार ने जम्मू-कश्मीर को इतने भागों में बाँट दिया - दो
- संविधान का वह अनुच्छेद जिसे हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हटा दिया है - अनुच्छेद 370
- वह मंत्रालय जिसके तहत आदर्श स्मारक योजना शुरू की गई है - संस्कृति मंत्रालय
- वह उत्पाद जिसे हाल ही में BIS प्रमाणपत्र दिया गया है - पश्मीना उत्पाद
- वह मंत्रालय जिसने संकल्प योजना शुरू करने की घोषणा की है - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- वह देश जिसने इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से हटने की घोषणा की है - अमेरिका
- भारत के घरेलू बाजार को महत्त्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के इतने केंद्रीय प्रतिष्ठानों ने (Khanij Bidesh India Ltd-) KABIL की स्थापना करने की घोषणा की - तीन
- प्रत्येक वर्ष दुनियाभर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है - 1 से 7 अगस्त तक
- केंद्र सरकार द्वारा घोषित Human Genome Mapping Project के तहत स्कैन किये जाने वाले लोगों की संख्या - 20,000
- वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने वारसा में खेली जा रही कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है - विनेश फोगाट
- वह कंपनी जिसने हाल ही में 'जीवन अमर' इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है - एलआईसी ऑफ इंडिया
- वह देश जिसे अमेरिका ने "करेंसी मैनीपुलेटर" या मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया - चीन
- इनकी अध्यक्षता में UGC की 542वीं बैठक का आयोजन किया गया - एन गोपालस्वामी
- इन्हें हाल ही में अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स का निदेशक नियुक्त किया गया है - आतिश दाभोलकर
- टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं - विराट कोहली
- वह राज्य जहाँ रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है - कर्नाटक
- वह स्वीडिश Anti & Plagiarism सॉफ्टवेयर जिसकी भारत के सभी विश्वविद्यालयों को 1 सितंबर, 2019 से सदस्यता मिलेगी - न्तानदक
- वह राज्य जहां भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण को लगभग 3,600 साल पहले की ग्रामीण बस्ती का पता चला - ओडिशा
- वह संस्था जिसने हाल ही में किये शोध Economics of Desertification, Land Degradation and Drought in India* नामक रिपोर्ट जारी की -TERI
- भारत की पूर्व विदेश मंत्री जिनका हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया - सुषमा स्वराज
- RBI के नए मौद्रिक नीति के अनुसार अब से रेपो रेट की दर होगी - 5.40 प्रतिशत
- फोर्ब्स पत्रिका की खेलों में सबसे अधिक भुगतान वाली महिलाओं की सूची में इस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है - सेरेना विलियम्स
- ललित कला अकादमी का स्थापना दिवस मनाया गया - 65वां
- नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा जिस 'सुपर अर्थ' की खोज की गई है उसे दिया गया नाम है - GJ 357d
- हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किये गए वीडियो गेम का नाम है - Indian Air Force: A Cut Above
- वह राज्य जिसने मध्य प्रदेश के बाद हाल ही में मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित किया है - राजस्थान
- भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाने वाला दिवस है - राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस
- वह देश जिसने भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है - पाकिस्तान
- इन्हें इस वर्ष वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा - विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान
- वह देश जिसके द्वारा पाकिस्तानी डॉक्टरों की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की मान्यता रद्द करके उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया है - सऊदी अरब
- मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 के अनुसार मोटर वाहनों से संबंधित दंड शुल्क में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि दर होगी - 10 प्रतिशत
- ऑस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार बीते 15 वर्षों में विश्वभर में मारे जाने वाले पर्यावरणविदों की संख्या है - 1558
- भारत में जन्मीं तथा अब इंग्लैंड में बस चुकी महिला जिन्हें मिस इंग्लैंड 2019 के खिताब से नवाजा गया है - भाषा मुखर्जी
- पाकिस्तान में तैनात भारतीय उच्चायुक्त जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारत वापिस भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया है - अजय बिसारिया
- संसद द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक - 2019 के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने पर सेलिब्रिटीज पर अधिकतम जुर्माना लगाये जाने की रकम है - 50 लाख रुपये
- वह शहर जहां ई-गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है - शिलांग
- भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें हाल ही में भारत रत्न - 2019 से सम्मानित किया गया - प्रणब मुखर्जी
- देश के महान संगीतकार जिन्हें भारत रत्न - 2019 मरणोपरांत दिया गया है - भूपेन हजारिका
- खेल मंत्रालय द्वारा सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए बनाई गई एक चयन समिति में सदस्यों की संख्या होगी - 12
- दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज का नाम जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की - हाशिम अमला
- मणिपुर की 09 वर्षीय बच्ची का नाम जिसे हाल ही में 'मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन' का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है - एलंगबाम वेलेंतिना देवी
- वह राज्य सरकार जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति 15 जीबी डाटा प्रतिमाह मुफ्त देने की घोषणा की गई है - दिल्ली सरकार
- वह राज्य सरकार जिसने 'मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना' शुरु करने को मंजूरी दे दी है - उत्तर प्रदेश
- श्रीनगर सेंट्रल जेल में जगह की कमी हो जाने के बाद 25 कैदियों को जिस स्थान पर स्थानांतरित किया गया है - आगरा सेंट्रल जेल
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अगला चरण 2020 से लेकर जिस वर्ष तक पूरा किया जायेगा - 2025
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या है - 453
- भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए जिस नाम से पहल आरंभ की गई है - समर्थ
- भारतीय चाय बोर्ड थोक चाय की ई-नीलामी प्रणाली में सुधार के लिये जिस देश के ई-नीलामी प्रणाली को अपनाने पर विचार कर रहा है - जापान
- भारत में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु जिस आयोग के कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन के तहत अटल समुदाय नवाचार केन्द्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई है - नीति आयोग
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 300 अरब डॉलर के चाइनीज आयात पर जितने फीसदी टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की है -10 फीसदी
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन अगले वर्ष 18 से 30 जनवरी तक जिस शहर में किया जाएगा - गुवाहाटी
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के निदेशक मंडल के जिस सदस्य को प्राधिकरण के चेयरमैन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गयी है - अनुज अग्रवाल
- जिस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड के लिए चयनित किया गया है - रवीश कुमार
- हाल ही में वह देश जिसने पुरुष संरक्षक की अनुमति के बिना महिलाओं को यात्रा की इजाजत दी है - सऊदी अरब
- सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत के जिस राज्य में भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग के लिए ड्रोन से सर्वे किया जायेगा - महाराष्ट्र
- 52वीं आसियान विदेश मंत्री बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया जा रहा है - बैंकॉक
- हाल ही में जारी वॉटर स्ट्रेस इंडेक्स के मुताबिक, देश के जितने बड़े शहरों में से 11 शहर जल संकट की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं - 20
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर जितने किए जाने की मंजूरी दे दी है - 33
- भारत ने कौशल विकास और कुटीर उद्योग परियोजना के लिए गाम्बिया को जितने लाख अमेरिकी डॉलर की मदद देने की घोषणा की - पाँच लाख
- तीन तलाक देने वाले पति को अधिकतम जितने साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है - तीन साल
- हाल ही में जिस राज्य के पुलिस ने स्वचालित मल्टी-मोडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली अपनाई है - महाराष्ट्र पुलिस
- वित्त मंत्रालय ने हाल ही में दक्षिण कोरिया और जिस देश से आयात होने वाले शुद्ध PTA (Pure Terephthalic Acid) पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है- थाईलैंड
- हाल ही में चीन और जिस देश के बीच शंघाई में व्यापार मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई है - अमेरिका
- फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने महिलाओं के अगले फुटबॉल विश्व कप में टीमों की संख्या 24 से बढ़ाकर जितने करने को अनुमति दे दी है - 32
- हाल ही में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे द्वारा खोजे गए बौने तारे और ग्रहीय प्रणाली का यह नाम रखा गया है - TOI 270
- वह देश जिसकी सेना ने युद्ध में बेहतर प्रदर्शन और दुश्मन पर त्वरित आक्रमण करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिये 'पहले एकीकृत युद्ध समूह का गठन करने का फैसला किया है - भारतीय सेना
- विश्व भर में प्रसिद्ध जिस राज्य में पाए जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है - राजस्थान
- हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पारित किया जिसका उद्देश्य राज्य के जितने निजी विश्वविद्यालयों को एक ही कानून के अंतर्गत लाना है - 27
- जिस देश में बैटरी उत्पादन के लिये टेस्ला शैली की कम से कम चार गीगाफैक्टरीज स्थापित करने हेतु करीब 4 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी - भारत
- सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में संशोधन करके अब जितने लाख रुपए वार्षिक आय वालों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करने का निर्देश दिया है - पाँच लाख
- 8500 फीट की ऊंचाई से विंगसूट जम्प करने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट का नाम यह है - तरुण चौधरी
- वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसको बीसीसीआई द्वारा हाल ही में डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद आठ महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है - पृथ्वी शॉ
- कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ का शव हाल ही में दक्षिण भारत की जिस नदी से मिला है - नेत्रावती नदी
- केंद्र सरकार द्वारा जिस भाषा के कलाकारों को फेलोशिप दिए जाने की श्रेणी में शामिल किया गया है - संथाली
- जिसे हाल ही में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है - राजीव कुमार
- हाल ही में केंद्रीय जल मंत्री ने जिस राज्य में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की क्षमता सुदृढ़ीकरण पहल की शुरुआत की - झारखंड

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- हर घर में नल से जल योजना के तहत हिमाचल मे केंद्र सरकार कितने प्रतिशत खर्च का वहन करेगी - 90 प्रतिशत
- हिमाचल में शिक्षण संस्थानों में कितने मीटर तक तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध है - 100 मीटर तक
- रेड सिंधी किसकी नस्ल है - गाय की
- पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी पाजपेयी की प्रतिमा कहां बनाई जाएगी - मनाली में
- सिरमौर जिला में नाहन में करीब 4300 करोड़ रूपये के घोटाले को लेकर हाल ही में कौन सी कंपनी चर्चा में है - टैक्नोमैक कंपनी
- जंगी थोपन बिजली प्रोजेक्ट किस जिले में है - किन्नौर में 960 मेगावाट
- प्रदेश की एकमात्र भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस जिले में है - किन्नौर में नाथपा झाकड़ी परियोजना, 1500 मेगावाट
- हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा गठित पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के चेयरमैन कौन है - आषा ठाकुर
- मुख्यमंत्री हरित विद्यालय पौधारोपण अभियान की शुरूआत किस जिले से की गई है - राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोह, ऊना
- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किससे मंडी में प्रस्तावित अंतरराश्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया - 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से
- बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हिमाचल के किन तीन जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा - शिमला मंडी और सिरमौर
- हिमाचल में सरकारी स्कूलों को स्टार प्रोजेक्ट द्वारा कंप्यूटराइज्ड करने के लिए किसके द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी - विश्व बैंक
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संशेधित आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है - 45 वर्ष
- तुंगल घाटी कहां पर है - मंडी
- हिमाचल के किस मेडीकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा षुरू की गई - इंदिरा गांधी मेडीकल कॉलेज
- नीति आयोग द्वारा देश के 64 शहरों में ई बस सेवा के तहत हिमाचल के कितने शहरों को षामिल किया गया - शिमला और हमीरपुर
- हिमाचल में पहला गद्दी भेड़ फार्म कहां खोला जाएगा - ज्यूरी शिमला
- कृमि नाशक अभियान में हिमाचल ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है - पहला
- हिमाचल में कितने प्रतिशत भूमि वनों के अधीन है - 68.16 प्रतिशत
- हरणातर किस जिले का लोकनाट्य है - चंबा
- हिमाचल के अधिकतर वौद्ध अनुयायियों का संबंध किससे है - वज्रयान से

सामार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

हिमाचल प्रदेश महिला स्वरोजगार योजना

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को अपना रोजगार उपलब्ध कराने में मदद पहुंचाने के उद्देश्य से स्वयं रोजगार सहायता योजना शुरू की है। स्वयं रोजगार सहायता योजना में ऐसी महिलाओं को 2500 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। यह आर्थिक मदद उन लोगों को दी जाती है जिनके परिवार की सालाना आय 35,000 रुपये से कम हो। खास बात यह कि इस आमदनी में मनरेगा से हुई कमाई शामिल नहीं है। अगर ऐसी महिला अपना कोई छोटा-मोटा कारोबार करना चाहती हो उन्हें हिमाचल सरकार से स्वयं रोजगार सहायता योजना में मदद मिल सकती है।

क्या है स्वयं रोजगार सहायता योजना का उद्देश्य?

समाज के कमजोर तबके की महिलाओं को वित्तीय मदद देकर चाय-नाश्ते की दुकान, सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, कढ़ाई-बुनाई आदि जैसे काम करके अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में योगदान करने के उद्देश्य से स्वयं रोजगार सहायता योजना शुरू की गयी है।

क्या है रोजगार चुनने का जरिया?

हिमाचल में हर पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। इन ग्राम सभाओं में पंचायत प्रतिनिधि गांव के सभी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। इसके अलावा कई विकासात्मक योजनाओं पर भी ग्रामसभा के दौरान चर्चा की जाती है। ग्राम सभा में चर्चा का मुख्य मुद्दा रोजगार है। ग्राम सभा में जन-प्रतिनिधियों के सामने चर्चा कर महिलाएं अपने लिए

रोजगार के अवसर और विकल्प पर बातचीत कर सकती हैं। इसमें महिलाएं अपने लिए योजना बनाएंगी और इन योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हें वित्तीय मदद देगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना चलाई जाती है। ग्राम सभा साल में दो बार आयोजित होती है।

महिलाओं के लिए स्व रोजगार के कौन से हैं विकल्प?

महिला ग्राम सभा में पंचायत में सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पार्क, पंचायतों का सौंदर्यीकरण, डेयरी फार्म, कढ़ाई-बुनाई, चाय-नाश्ते की दुकान जैसे स्व रोजगार के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। इन प्रस्ताव को पारित करने के बाद मामला आम सभा में जाएगा, जहां इसे स्वीकृति दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में 3226 ग्राम पंचायत हैं, जहां साल में दो बार यह सभा होनी है।

कैसे करें स्वयं रोजगार सहायता योजना में आवेदन?

हिमाचल सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं अपने इलाके की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाईजर से संपर्क कर सकती हैं। महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए सीधे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर (जिला कार्यक्रम अधिकारी) से भी मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के बाल विकास अधिकारी से भी योजना संबंधी मदद

ली जा सकती है। स्वयं रोजगार सहायता योजना में आवेदन करने के लिए योग्यता महिला हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी हो। महिला की उम्र 18 साल से अधिक हो। महिला के परिवार की कुल आमदनी 35,000 रुपये से कम हो। परिवार का खर्च चलाने के लिए महिला काम करने की योजना बना रही हो।

किन दस्तावेजों की है जरुरत?

फोटो आईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड आवेदन पत्र हिमाचल सरकार वास्तव में स्व रोजगार सहायता योजना के जरिये प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। स्व रोजगार के प्रयास करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गयी है। राज्य की कोई भी महिला इस योजना के तहत सरकार से मदद ले सकती है।

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब लोगो को गंभीर बिमारीयों इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे कैंसर, पार्किंसन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसिमिया, हीमोफिलिया और रीनल फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का उपचार करा सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के लाभ

- इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार के लोगो को ही दिया जायेगा जिनकी सालाना आय 4 लाख रुपये से कम है।
- इस योजना के तहत इलाज के लिए आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपये प्रति माह प्रदान किये जायेंगे।
- प्रथम चरण में इस योजना के तहत लगभग 6000 लोगो को कवर किया जायेगा।
- योजना के अनुसार तय की गई आर्थिक सहायता राशी लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- योजना के अनुसार गरीब लोग कई गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकेंगे जैसे -कैंसर, पार्किंसन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसिमिया, हीमोफिलिया और रीनल फेलियर।

योजना के लिए जरूरी पात्रता

- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से निचे है।
- लाभार्थी की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

कैसे आवेदन करे

- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपनेनजदीकी जिला चिकित्सा अधिकारी के पास जरूरी प्रमाण-पत्र जमा करवाने होंगे, जिसके बाद वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आवेदन सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, बैंक डिटेल।

इस योजना का लाभ राज्य के अधिक से अधिक लोगो को प्रदान करने के लिए आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर घर-घर जाकर लोगों इस योजना की जानकारी देंगे जिसके लिए सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को प्रति लाभार्थी 200 रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने एचआईवी एड्स से पीड़ित मरीजों के भत्ते को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है।

अनुभव योजना

हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से मिलने का समय और तारीख जैसी सुविधा मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगी। बीते साल सितंबर के पहले हफ्ते में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुभव योजना शुरू की है। यह वास्तव में एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। हिमाचल के नागरिक अनुभव योजना के तहत घर बैठे डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं। यह वास्तव में एक टोकन के जरिये होता है जिसमें आप डॉक्टर से समय लेकर अपनी सुविधा के हिसाब से

उनसे दिखाने जा सकते हैं। अनुभव योजना कुल्लू जिला अस्पताल में शुरू की गई। जल्द ही इसे प्रदेश के सभी अस्पतालों में लागू करने की तैयारी की जा रही है।

क्या है अनुभव योजना का उद्देश्य?

हिमाचल सरकार नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ सेवा को बढ़ावा देना चाहती है। डिजिटल हेल्थ सेवा की तरफ कदम बढ़ाते हुए पहले कदम के रूप में अनुभव योजना शुरू की गयी है। अब लोगों को अस्पताल में डॉक्टर से दिखाने के लिए लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

कैसे काम करती है अनुभव योजना?

स्वास्थ्य विभाग की अनुभव योजना वास्तव में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की तरफ बढ़ता कदम है। ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से अनुभव योजना में मरीज ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ही विशेषज्ञ डॉक्टर से अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इसके साथ ही मरीजों को मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से डॉक्टर से मिले समय की पुष्टि की जाएगी।

क्या होगा अनुभव योजना से लाभ?

अगर आपने ऑनलाइन सुविधा की मदद से किसी डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट लिया है और किसी वजह से डॉक्टर से मिलने वाली तिथि या समय में कोई बदलाव किया गया तब भी आपको इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। वास्तव में अनुभव योजना के तहत अप्वाइंटमेंट फिक्स करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ई-पर्ची जेनरेट होगी। इसे दिखाकर डॉक्टर से इलाज कराया जा सकेगा।

कैसे लें डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट?

अगर आपके पास स्मार्टफोन कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो अनुभव योजना के जरिये डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप आशा वर्कर की मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस पेज की मदद से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। : https://ors-gov-in/index.H-html अनुभव योजना के अन्य फायदे दूर दराज के इलाके से अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर से नहीं मिल पाने वाले मरीजों का समय और पैसा बचाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश सहारा योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बीपीएल परिवार के गरीब लोगो को स्वस्थ्य सम्बंधि सहायता प्रदान करने के लिए एक नयी योजना शुरू की है नाम है “सहारा योजना”। हालाँकि पहले से ही राज्य के गरीब लोगो को केंद्रीय सरकार की आयुष्मान भारत योजना और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की हिम केयर योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद भी राज्य के गरीब को इलाज के लिए सहारा योजना के तहत प्रति माह 2000 रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

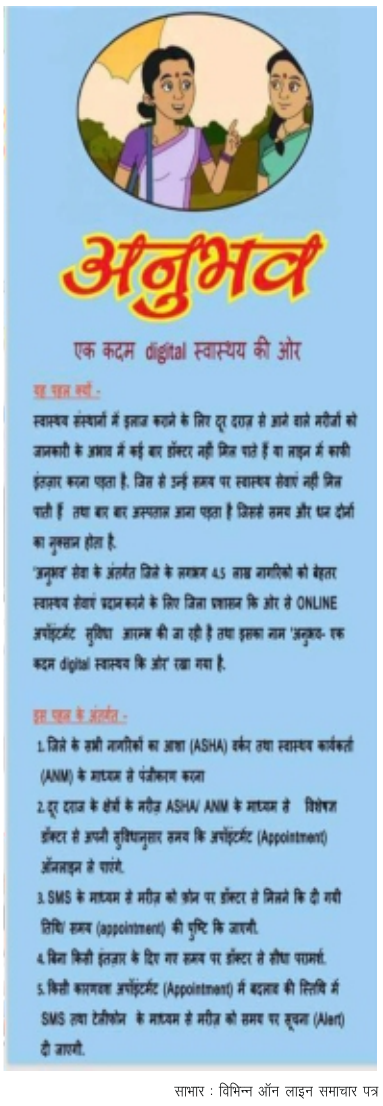

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सौभाग्य योजना

देश में एक ओर बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है तो दूसरी ओर यह भी बड़ी हकीकत है कि आजादी के सात दशकों बाद भी भी करीब चार करोड़ ऐसे घर हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंच पाई है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल भी इस सूची में शामिल है जहां कुछ गांवों के लोग आज भी लालटेन के मधम उजाले से अपने जीवन को रोशन करते हैं। बच्चे पढ़ाई भी मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी में करते हैं तो महिलाएं भी बिना बिजली के पेरशानी झेलने को मजबूर रहती है।

शायद ग्रामीण भारत की इसी सबसे बड़ी परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना की शुरूआत की। उम्मीद है कि जिस प्रकार उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं के जीवन को ना सिर्फ धुएँ से मुक्ति दिलाकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की बल्कि उनका जीवन भी आसान बनाया उसी प्रकार सौभाग्य योजना भी ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में कामयाब रहेगी। आइए जानते हैं सौभाग्य योजना क्या है और इसका लाभ किसको और कैसे मिलेगा।

क्या है सौभाग्य योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित की गयी इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। जिन लोगों का नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में है उन्हें इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जायेगा। जिन लोगों का नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना में नहीं है उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें बिजली का कनेक्शन मात्र 500 रुपए देकर मिल सकता है और यह 500 रुपए भी वह दस आसान किस्तों में दे सकते हैं। जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां इस योजना के तहत सरकार की ओर से हर घर को एक सोलर पैक दिया जाता है जिसमें पांच एलईडी बल्ब और एक पंखा है। बिजली से वंचित चार करोड़ घरों की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने इस योजना के लिए 16 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है।

इस योजना के तहत सरकार मिट्टी के तेल का विकल्प भी बिजली को बनाएगी। इसके लिए सरकारी कंपनी ओएनजीसी की ओर से नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए अच्छा खासा फंड रखा गया है। सरकार चाहती है कि युवा घरेलू काम में आने वाले और कम ऊर्जा खपत वाले बिजली के उपकरण बनाएं। इस योजना की अन्य मुख्य बातों में शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जनता की सुरक्षा और संचार के साधन को और बेहतर बनाना तथा मुख्य रूप से रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है।

सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिये लोगों को खासकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा क्योंकि जब घरों में रोशनी नहीं, बिजली कनेक्शन नहीं तो इसका सीधा असर रास्तों की रोशनी पर भी पड़ता है। अंधेरे में घर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है। विशेषकर महिलाएं तो जैसे घर में ही बंद होकर रह जाती हैं। इस योजना के अनुसार बिजली की उपलब्धता को पूरा करने का लक्ष्य 2019 तक रखा गया है। केंद्रीय ऊर्जा सचवि ए के भल्ला के अनुसार केंद्र देश के हर घर में बिजली को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। देश भर में लगभग 73.38 प्रतशित घरों में बिजली का कनेक्शन है।

योजना का नाम – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

किसके द्वारा घोषित की गयी– केंद्रीय सरकार द्वारा लांच

कब हुई : 25 सितंबर 2017

योजना का लक्ष्य : भारत के हर घर में बिजली पहुंचाना

किसको मिलेगा फायदा : गरीब लोगों को

क्या होगा आपको फायदा? : इस योजना के तहत देश के सभी गांवों का बिजलीकरण होगा।

इसके तहत ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स और तारों के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर 16, 320 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें बजटीय सहायता 12, 320 करोड़ रुपए है। जहां बिजली नहीं जा सकती वहां

'सौलर पैक' दिया जा रहा है। 5 एलईडी लाइटें, एक डीसी पंखा, एक डीसी पावर प्लग और पांच वर्ष तक इसकी मुरम्मत का खर्च सरकार की ओर से प्रावधान है। बिजली कनेक्शन के लिए हर गांव में कैंप लगाया जाता है। योजना से गांव में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और गरीब 10 किश्तों में भी पैसे दे सकते हैं। बिजली बिल के लिए स्मार्ट और पेड मीटर लगाया जाता है। योजना के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

ये हो रहे फायदे

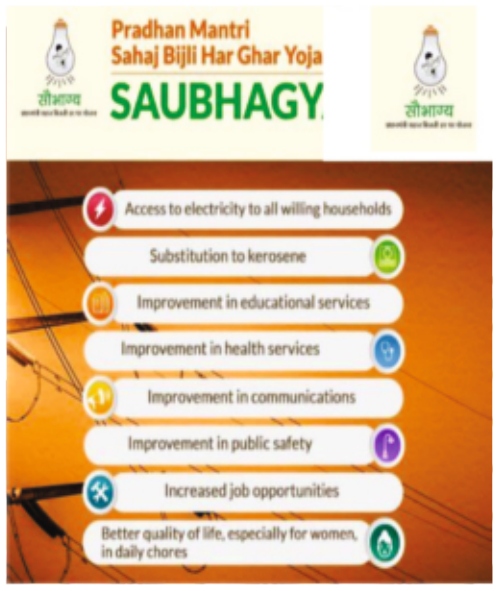

योजना से पर्यावरण की स्थिति में सुधार हो रहा है। बिजली उपलब्ध होने से लोग ईंधन का उपयोग कम करते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में मोबाइल, रेडियो और टेलविजिन के माध्यम से केनेक्टीविटी बढ़ेगी। आर्थिक गतविधियों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ ही महिलाएं होगी और विशेष रुप से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। योजना से जुड़ने के लिए मोबाइल एप्प का इस्तेमाल किया जाता है और इसी एप्प के जरिए आवेदन भी स्वीकार किए जाते हैं।

योजना का शुभारंभ

इस स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने लांच किया है। इस स्कीम की घोषणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर की गयी है। इस स्कीम के तहत सरकार गांवों के साथ–साथ सभी शहरी इलाकों में भी बिजली पहुंचाएगी। इस स्कीम को सही तरह से चलाने की जिम्मेवारी ग्रामीण विद्युत निगम को दी गयी है और ये निगम इस स्कीम को सफल बनाने के लिए हर कार्य कर रहा है।

योजना से जुड़े दस्तावेज

इस स्कीम का लाभ लेने के लिए नीचे बताये गए दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी, इसलिए इन सब को रखना अनविार्य है :

आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, मोबाइल नंबर बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस।

सौभाग्य योजना के तहत चयनित इलाके की सूची:

बिहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्य

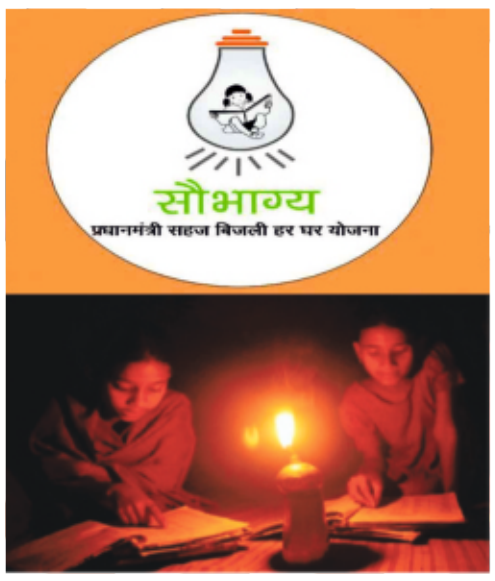

सौभाग्य योजना का उद्देश्य

शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जनता की सुरक्षा और संचार के साधन को और बेहतर बनाना है। मुख्य रूप से सरकार सौभाग्य योजना के जरिये सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। सौभाग्य योजना से लोगों, खासकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा। अंधेरे में घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, खास तौर पर महिलाएं अंधेरे में घर से निकलना नहीं चाहती। सरकार खुद गरीब परिवार के घर पर आकर बिजली कनेक्शन देने की पहल कर रही है। जिस बिजली कनेक्शन के लिए गरीब लोगों को मुखिया और सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, उन्हें अब आसानी से बिजली कनेक्शन मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव में हर शहर में हर घर में बिजली प्रदान करना है। सरकार ने 31 मार्च 2019 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

सरकारी कंपनियों का योगदान

सरकारी कंपनी ओएनजीसी की ओर से इन्नोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए भी बड़ा फंड रखा गया है। सरकार चाहती है कि युवा घरेलू काम में आने वाले और कम ऊर्जा खपत वाले बिजली के उपकरण बनाने की पहल करें।

योजना से जुड़ा वेब पोर्टल

स्कीम पर निगरानी रखने के लिए, इस स्कीम की प्रोग्रेस की जानकारी हासिल करने के लिए और स्कीम के लिए खुद का रजस्ट्रिेशन करवाने के लिए एक वेब पोर्टल http://saubhagya-gov-in/ भी बनाया गया है। इस पोर्टल को 16 नवंबर 2017 को लांच किया गया था। इस वेब पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ति बिजली कनेक्शन लेने के लिए अपना नाम पंजीकरण करवा

सकता है। इतना ही नहीं समय समय पर इस वेब पोर्टल पर जाकर ये भी जानकारी प्राप्त कर सकता हैं कि उसको कब तक बिजली दी जाएगी। योजना से जुड़ी मोबाइल एप्प वेब पोर्टल पेज के अलावा इस स्कीम से जुड़ी एक मोबाइल एप्प भी हैं। जिसके जरिए भी लोग इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।

मोबाइल एप्प के जरिए कैसे करें पंजीकरण

इस स्कीम के लिए अगर आप मोबाइल एप्प के जरिए अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्कीम से जुड़ी एप्प को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। अब उस एप्प में दिए गए एक फार्म को भरना होगा और फॉर्म को सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रीसिटी कनेक्शन लेने के लिए हो जाएगा।

हासिल किया गया लक्ष्य

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर स्कीम की तय सीमा अगले साल तक खत्म होने वाली है और इस समय तक सरकार ने 60 लाख से अधिक घरों को एलेक्ट्रीफाएड कर दिया है। जबकि 3,20,45,929 घरों को एलेक्ट्रएिड किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

8 राज्यों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया

केन्द्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह की ओर से जारी बयान के मुताबिक सौभाग्य योजना के अंतर्गत 8 राज्यों ने 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया हैं। इसके साथ, देश में अब कुल 15 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो गया है। ये आठ राज्य मध्यप्रदेश ,त्रिपुरा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत अब तक 2.1 करोड़ कनेक्शन जारी किये गये।

पूर्ण विद्युतीकरण से वंचित

महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विद्युतीकरण से वंचित घर कम संख्या में बचे हैं और उम्मीद है कि सभी घरों का विद्युतीकरण हो जायेगा। विद्युतीकरण की वर्तमान गति के मुताबिक देश के सभी 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसम्बर 2018 तक पूरा हो जायेगा।

सौभाग्य योजना के तहत पुरस्कार योजना:

विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों / राज्य के विद्युत विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए 300 करोड़ रूपये की पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियां / विद्युत विभाग को कर्मचारियों के लिए 50 लाख का पुरस्कार और वितरण संरचना पर खर्च के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा। पुरस्कार के उद्देश्य से राज्य को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और इन सभी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे।

पुरस्कार तीन श्रेणियों में

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF POWER

पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे। यह श्रेणियां हैं:

- डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों (7 पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) के विद्युत विभाग को दिए जाएंगे।
- डिस्कॉम/विशेष दर्जा के अलावा अन्य राज्यों (बिहार,छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) जिनमें विद्युतीकरण से वंचित पांच लाख से अधिक घर है।
- डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य जहां पांच लाख से कम घर विद्युतीकृत नहीं हैं।
- 31 दिसम्बर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का काम करने वाले राज्यों को सौभाग्य के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सड़क किनारे क्यों लगे होते हैं अलग–अलग रंग के मील पत्थर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सड़क किनारे लगे माइल स्टोन यानी मील के पत्थरों को तो आपने देखा ही होगा, जिस पर किसी स्थान की दूरी और उस जगह का नाम लिखा होता है। इन पत्थरों के ऊपरी हिस्से पर पीला, हरा, काला और नारंगी रंग होता है, जबकि सभी पत्थरों के निचले हिस्से सफेद रंगों से रंगे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर माइल स्टोन के ये पत्थर अलग–अलग रंगों के क्यों होते हैं?

अक्सर हाइवे या किसी भी गांव से गुजरते समय आप ऐसे पत्थरों को देखते होंगे। हालांकि उस पर लिखी दूरी के अलावा और किसी चीज पर खास ध्यान नहीं देते, लेकिन हम आपको बता दें कि अलग–अलग रंग के ये पत्थर बहुत काम के होते हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं।

अगर सड़क पर चलते वक्त या ड्राइव करते वक्त किनारे पर ऐसा पत्थर दिखे, जिसका ऊपरी हिस्सा पीले रंग का हो तो समझ जाइए कि आप नेशनल हाइवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं।

जब आपको सड़क पर हरे रंग का मील का पत्थर दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं बल्कि राज्य राजमार्ग या स्टेट हाइवे पर चल रहे हैं।

जब आपको सड़क पर काले या नीले और सफेद रंग की पट्टी वाला पत्थर दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं।

जब आपको सड़क के किनारे नारंगी रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन या मील का पत्थर दिखता है तो समझ जाइए कि आप किसी गांव या फिर गांव की सड़क पर हैं।

चांद पर नहीं मिटते इंसानों के पैरों के निशान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

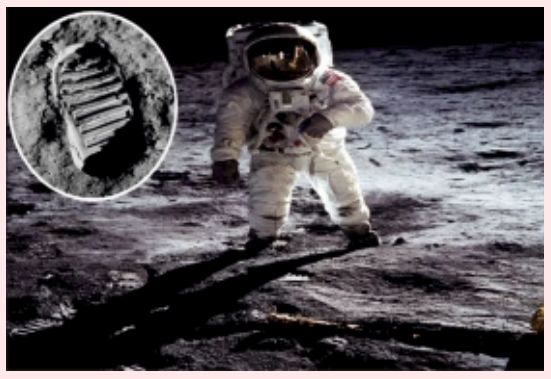

ये तो सब जानते हैं कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं, जबकि अंतरिक्ष यात्री यूजीन सेरनन आखिरी व्यक्ति थे, जिन्होंने साल 1972 में चंद्रमा की सतह पर अपने कदमों के निशान छोड़े थे। इस बात को अब 46 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके पैरों के निशान आज भी चांद की धरती पर मौजूद होंगे। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। इसके निर्माण के पीछे भी एक अनोखी कहानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 450 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट कर अलग हो गया और वही हिस्सा बाद में जाकर चांद बना।

वैज्ञानिकों के मुताबिक, चंद्रमा का सिर्फ 59 फीसदी हिस्सा ही पृथ्वी से दिखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर चांद अंतरिक्ष से गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन मात्र छह घंटे का रह जाएगा।

आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि चांद के रोशनी वाले हिस्से का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि अंधेरे भाग का तापमान –153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्सन बताते हैं, चंद्रमा मिट्टी की चट्टानों और धूल की एक परत से ढंका हुआ है। साथ ही मिट्टी के कण भी इस परत में मिश्रित होते हैं, इसलिए चांद की सतह पर से पैर के हट जाने के बाद भी पैरों के निशान बने रहते हैं।

मार्क रॉबिन्सन का कहना है कि चंद्रमा पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के पैर के निशान लाखों सालों तक वैसे ही रहेंगे, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है।

ऑस्ट्रिया में है दुनिया की सबसे लंबी हिम गुफा

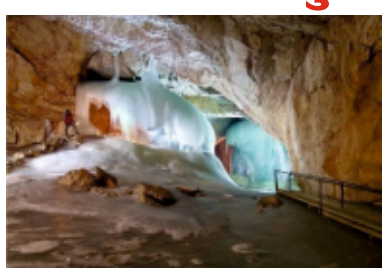

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमरनाथ तीर्थ स्थल के शिवलिंग के बारे में तो हर कोई जानता है, जहां बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ के शिवलिंग की तरह ही एक और शिवलिंग कहीं और भी है, जिसे देखने दुनियाभर से लोग आते हैं। दरअसल ऑस्ट्रिया के सल्जबर्ग शहर के पास वरफेन में एक 40 किलोमीटर लंबी हिम गुफा है, जिसमें कुदरती शिवलिंग जैसी आकृति बनी है। यह आकृति अमरनाथ के शिवलिंग से कई गुना बड़ी है। यह दुनिया की सबसे लंबी हिम गुफा है। इसे साल 1879 में खोजा गया था। यहां शिवलिंग की तरह दिखने वाली कई आकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। यह हिम गुफा मई से अक्टूबर तक खुली रहती हैं। यहां आपको गर्मी के महीनों में भी ठंड का अहसास होगा। इस गुफा में आकर आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप किसी अलग दुनिया में आ गए हों।

दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब वॉयनिक मैनुस्क्रिप्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों को तो इंसानों ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं, जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसा ही रहस्य है 240 पन्नों की एक किताब, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इतिहासकारों के मुताबिक, यह रहस्यमयी किताब 600 साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया है। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इसे वॉयनिक मैनुस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़–पौधों तक के कई चित्र बनाए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि किताब में कुछ ऐसे भी पेड़–पौधों के चित्र बनाए गए हैं, जो धरती पर मौजूद किसी भी पेड़–पौधे से मेल नहीं खाते।

इस किताब का नामश्वॉयनिक मैनुस्क्रिप्ट इटली के एक बुक डीलर विलफ्रीड वॉयनिक के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही इस रहस्यमयी किताब को साल 1912 में कहीं से खरीदा था।

कहा जाता है कि इस रहस्यमयी किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं। इस किताब के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि किताब में लिखे गए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में हैं।

दुनिया के सबसे अधिक और कम सोने वाले जीव

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंसान भोजन के बिना तो ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना नींद के यह संभव नहीं है। वैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो सामान्य मनुष्य अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोने में बिता देता है। वैसे आमतौर पर इंसानों के लिए आठ घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग इससे भी ज्यादा समय या कोई–कोई तो महज चार–पांच घंटे ही सोते हैं, लेकिन ऐसे इंसानों में असमय मृत्यू की संभावना बढ़ जाती है, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं है। उनके अंदर कई घंटों तक सोने की क्षमता रहती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दुनिया के सबसे अधिक और सबसे कम सोने वाले जीवों के रूप में विख्यात हैं। ये है नाईट मंकी। इनकी आंखें उल्लू की तरह और पूरा शरीर एक बंदर की तरह होता है। यही वजह है कि यह रात में भी देखने में सक्षम होते हैं। ये अधिकतर पनामा और उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका में पाये जाते हैं। नाईट मंकी 24 घंटे में 17 घंटे सोने में ही बिता देते हैं। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अर्जेंटीना में पाये जाने वाले विशालकाय आर्माडिलो भी सोने में माहिर होते हैं। ये 24 घंटे में 18.1 घंटे सोते ही रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला भूरा चमगादड़। यह जीव 24 घंटे में 19.9 घंटा सोता है। ये है कोआला, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक तरह का भालू है। इसे दुनिया में सबसे अधिक सोने वाला जानवर माना जाता है। यह 24 घंटे में 22 घंटे सोता है। जिराफ को तो आपने चिड़ियाघर में बहुत देखा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ एक बार में पांच मिनट जबकि 24 घंटे में महज 30 मिनट ही सोते हैं।

यहां है बापू गांधी का खास मंदिर, हर रोज दिन में तीन बार होती है पूजा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

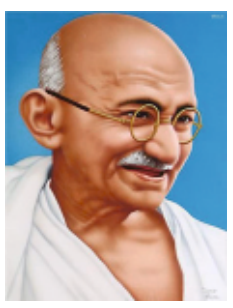

महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में उनके चाहने वाले हैं और उनकी याद में कुछ ना कुछ खास करते हैं। कुछ ऐसा ही खास है कर्नाटक के मंगलुरु में। यहां गांधी जी का एक खास मंदिर है, जिसमें हर रोज उनकी तीन बार पूजा होती है और आरती उतारी जाती है।

यह मंदिर मंगलुरु मे श्री ब्रह्म बैदरकला क्षेत्र गरोडी में बना हुआ है। महात्मा गांधी के अनुयायी इस मंदिर में आते हैं और उनके द्वारा बताए रास्ते (सत्य और अहिंसा) पर चलने का प्रण लेते हैं।

साल 1948 में यहां गांधी जी की एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की गई थी। बाद में साल 2006 में यहां लोगों की मांग पर मंदिर का निर्माण किया गया और साथ ही गांधी जी की संगमरमर की प्रतिमा लगाई गई।

जैसे किसी भगवान की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही इस मंदिर में गांधी जी की पूजा होती है। यहां दिन में तीन बार सुबह छह बजे, दोपहर 12 बजे और शाम के 7:30 बजे उनकी पूजा होती है। इसके अलावा गांधी जी की प्रतिमा के पास प्रतिदिन एक दीपक जलाया जाता है। गांधी जयंती के दिन इस मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। फल और मिठाइयों के साथ गांधी जी की प्रतिमा पर ब्लैक कॉफी चढ़ाई जाती है। बाद में, उसी कॉफी को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है।

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स

दूरभाष : 9418404334

Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़.....द रीव टाइम्स उत्कृष्ट गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर-द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट http://sub.missionriev.in पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता/अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500/रुपये, छः माह के लिए 250/रुपये में और घर बैठे पांऐ द रीव टाइम्स.....क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र